राजेश बिंदल और हरिंदनर सिंह सिद्धू से पहले, जे. जे.

राकेश पुनिया-याचिकाकर्ता

बनाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनय-प्रतिवादी

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. **24392**

21 दिसंबर, 2016

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **19 (1) (**सी**), 226**-अधिवक्ता अधिनियम, **1961**-एस. **S.**स **6 (1) (**डीडी**), 6 (1) (**एच**), 6 (1) (**आई**), 15,35,36** और **49**-अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, **2001**-एस. एस. **2 (**पी**), 2 (**क्यू**), 16,17,18,26** और **27**-बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस **(** जाच **)** नियम, **2015**-एस. एस. **4 (**ई**), 4 (**जी**), 6,8** और **28**-बार एसोसिएशन **(**संविधान और विनियमन**)** नियम, **2015**-बार एसोसिएशन चुनाव-अधीनस्थ विधान-वैधता-कानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण निर्माण और सख्त व्याख्या के नियम-**2015** के नियमों को चुनौती देना राज्य बार काउंसिल की अधिकार अधिकारातीत और नियम बनाने की शक्ति अधिकारातीत होना-यह बार एसोसिएशनों के चुनाव के संचालन को विनियमित नहीं कर सकता है जो वकीलों के निजी संघ हैं जो अपने स्वयं के उप-कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं-इसके अलावा, **2015** के नियमों को तैयार करने में प्रक्रियात्मक भंग हुआ था-आयोजित, कानून और नियम न केवल न्यायाधीश के प्रशासन में और आम तौर पर अधिवक्ता के हितों को बढ़ावा देने में बार एसोसिएशनों की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं, बल्कि वैधानिक और गैर-कानूनी कानूनों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव मे जैसे पेशे के **izR;sd** सदस्य तक पहुचने, शामिल करने और छूने वाले बार संघो के बिना **;kstukvkS** को लागू करना **vlaHko** होगा-शायद बार के निकाय को बढ़ावा देने के लिये राज्य बार संघो को सशक्त बनाने के इस एहसास के साथ **1961** के अधिनियम मे एस **6(1) (d)** को शामिल किया था । अधिनियम, **2001** के तहत कल्याणकारी योजनाओ को लागू करने के लिये एसोसिएशन एक वकील के लिये कल्याण निधि का सदस्य बनने के लिये

राजेश बिंदल और हरिंदनर सिंह सिद्धू से पहले, जे. जे

काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का सदस्य होना एक iwoZ 'krZ है -1961 अधिनियम की धारा 15 नियम iznku करती है । अधिनियम के खंड -2 ekeyks ds lEcU/k में बार काउंसिल पर अधिकार बनाना 1961 के अधिनियम या 2001 के अधिनियम के में कोई izko/kku पर विशेष रूप से बार एसोसिएशन के चुनावो के संबद्ध में नियम बनाने का अधिकार नहीं देता -एक अधीनस्थ की वैधता पर विचार करते समय विधान में न्यायालय को सक्षम अधिनियम की iz कृति, उद्देश्य vkSj योजना पर विचार करना होगा - यह सुनिशित करते हुये कि बनाए गए नियम मूल अधिनियम द्वारा परिचालित {ks= के भीतर हैं,न्यायालय को izko/kku को iZ भावी बनाने के लिए एक उद्देश्य iw.kZ fuekZ.k देना उचित gksxk । अधिनियम का उद्देश्य-यह माना गया है कि नियम बनाने की राज्य बार काउंसिल की शक्ति की सख्त व्याख्या करना कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा, जब तक कि विशिष्ट भाषा द्वारा दायरे में सीमित न हो-और एस. 15 के रूप में शक्ति को प्रत्यायोजित करने वाले प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं-इस बात पर जोर दिया गया है कि नियम बनाने की शक्ति को विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए एक व्यापक गुंजाइश दी जानी चाहिए-इन विचारों पर राज्य बार काउंसिल को ऐसे नियम बनाने का अधिकार दिया गया था जो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बार एसोसिएशनों के चुनावों से संबंधित मामलों में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए उनके उद्देश्य के रूप में हैं-वास्तव में ऐसे नियमों को तैयार करना संदर्भ के तहत अधिनियमों और नियमों द्वारा प्रमाणित व्यापक विधायी योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता मानी जा सकती है-आगे कहा गया, नियम बनाए गए है उपरोक्त उद्देश्य के साथ बार एसोसिएशन के चुनावों को नियमित करें, संविधान के अनुच्छेद 19(1) C के तहत वादियों के अधिकारो का उल्लंघन न करें , यह भी पाया गया कि नियम उनके लिए सभी वैधानिक iwoZ vko';drkvkS के अनुपालन के बाद बनाए गए थे। वैधता याचिका को इस fVIi.kh के साथ खारिज कर दिया गया कि न्यायालय 2015 के नियमों के O;fDrxr izko/kkuks dh वैधता पर नहीं गया ।

मान लिया कि उच्चतम न्यायाधीशालय के उपरोक्त कानूनों, नियमों और निर्णयों का संदर्भ स्पष्ट रूप से उस महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करता है जो बार एसोसिएशन न केवल न्याय के प्रशासन और आम तौर पर अधिवक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने में बल्कि उनके कल्याण के लिए वैधानिक या गैर-सांविधिक योजनाओं को लागू करने में भी निभाते हैं। वास्तव में ऐसी योजनाओं को बार एसोसिएशनों को संबद्ध किए बिना लागू करना असंभव होगा, क्योंकि यह केवल बार एसोसिएशन हैं जो पेशे के प्रत्येक अभ्यास करने वाले सदस्य तक पहुंचते हैं, उन्हें शामिल करते हैं और स्पर्श करते हैं।शायद यह इस तथ्य के अहसास में है कि खंड 6 (1) (डी. डी.) को 1961 के अधिनियम में 1993 (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ताकि राज्य बार काउंसिलों को अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(पैरा 39)

आगे कहा कि, 2001 के अधिनियम के अनुसार, राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का सदस्य होना अधिवक्ता कल्याण कोष का सदस्य बनने के लिए एक पूर्व शर्त है।खंड 16 के अनुसार, प्रत्येक बार एसोसिएशन, चाहे वह 2001 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले मौजूद हो या उसके बाद गठित हो, को राज्य बार काउंसिल के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।खंड 16 (3) के अनुसार मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संघ के नियमों और उपनियमों की एक प्रति होनी आवश्यक है।एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम और पते; एसोसिएशन के सदस्यों की एक सूची जिसमें नाम, पता, उम्र, नामांकन संख्या, नामांकन की तारीख और अभ्यास का सामान्य स्थान शामिल है।खंड 16 (4) के अनुसार, राज्य बार काउंसिल ऐसी जांच करने के बाद, जो उसे आवश्यक लगे, एसोसिएशन को मान्यता दे सकती है।किसी संगठन की मान्यता के संबंध में बार काउंसिल का निर्णय अंतिम बना दिया गया है।इस अधिनियम की खंड 17 प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ को हर साल 15 अप्रैल को या उससे पहले राज्य बार काउंसिल को अपने

राजेश बिंदल और हरिंदनर सिंह सिद्धू से पहले, जे. जे

सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है।खंड 17 (2) (सी) के अनुसार, प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ को राज्य बार काउंसिल को ऐसे अन्य मामलों के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो समय-समय पर राज्य बार काउंसिल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

(पैरा 40)

आगे कहा कि 2001 के अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार को उसकी धारा 35 और 36 के अनुसार प्रदान की गई है।हालाँकि, 1961 के अधिनियम की धारा 15 में अधिनियम के खंड II के मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, जिसमें धारा 3 से 15 शामिल हैं, बार काउंसिलों को प्रदान की गई है जिसमें भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिल शामिल हैं।यद्यपि खंड 15 (3) के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित न हो। (पैरा 41)

आगे कहा कि, एक बात स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी प्रावधान विशिष्ट शब्दों में राज्य बार काउंसिलों को बार एसोसिएशनों के चुनावों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है।सवाल यह है कि क्या बार काउंसिल के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत प्रदत्त खंड 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी नियम बनाने की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, विशेष रूप से धारा 6 (1) (डी. डी.) जो कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है; धारा 6 (1) (एच) जो अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त अन्य सभी कार्यों को करने से संबंधित है और धारा 6 (1) (आई) जो बार काउंसिल को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजें करने का अधिकार देती है। (पैरा 43)

यह भी माना गया कि किसी अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति का दायरा न्यायिक निर्णयों का विषय रहा है।यह माना गया है कि न्यायालय को एक अधीनस्थ विधान की वैधता पर विचार करते समय, सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना होगा, और यह भी कि जिस क्षेत्र पर राकेश पूनिया बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।और फिर यह तय करें कि अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम के अनुरूप है या नहीं।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करते हुए कि बनाए गए नियम मूल अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्र के भीतर हैं, न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण देने में उचित होगा।

(पैरा 44)

आगे कहा कि हम एल. डी. के तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 2015 के नियम अमान्य हैं क्योंकि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की कार्यवाही और एल. डी. द्वारा निर्दिष्ट संचार को ध्यान में रखते हुए। बार काउंसिल के वकील **us ik;k** कि नियमों की वैधता के लिए वैधानिक पूर्व-**'krkZs** का पालन किया गया था।नियम मसौदा समिति द्वारा तैयार किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा विचार किया गया, जिसने इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुमोदन के लिए भेजा।बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल हाउस ने 2.5.2015 पर आयोजित अपनी बैठक में इसे मंजूरी दी।

(पैरा 53)

आगे कहा कि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाओं के वर्तमान सेट द्वारा, हमने केवल बार एसोसिएशनों के चुनावों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल की क्षमता के सवाल को संबोधित किया है और यह माना है कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा निष्पक्षता और पारदर्शिता प्राप्त करने के

उद्देश्य से ऐसे नियम बनाने के माध्यम से बार एसोसिएशनों के चुनावों का विनियमन 1961 के अधिनियम के प्रावधानों **ds nk;js ls ckgj ugha gSA** यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत मूल अधिकार का भी उल्लंघन नहीं है।हम 2015 के नियमों के व्यक्तिगत प्रावधानों की वैधता में नहीं गए हैं क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत प्रावधान के संबंध में किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था।इसलिए इस निर्णय को 2015 के नियमों के प्रत्येक प्रावधान की वैधता पर राय और पुष्टि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(पैरा 55)

रमन शर्मा, गगनदीप राणा और दिव्य सरूप, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता के लिए।

D.K.Jangra और राकेश गुप्ता, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए-पी. बी. की बार काउंसिल और एच. आर.

हरिंदर सिंह सिधु, जे।

(1) यह निर्णय 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. Nos.5232,23865,24392 और 25912 का निपटारा करेगा क्योंकि इसमें इसी तरह के मुद्दे शामिल हैं।

(2) वर्तमान याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या बार एसोसिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियम, 2015 (संक्षेप में "2015 नियम") अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 अधिनियम") के तहत राज्य बार काउंसिल की नियम बनाने की शक्तियों **ls** परे हैं? और आगे क्या उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं?

(3) दिनांक 04.08.15 के फैसलें के तहत, इस न्यायालय ने 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6047, हरजोत सिंह वाली याचिकाओं के एक समूह का निपटारा किया था।हरिके बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बार काउंसिल औरअन्य संबंधित मामले जिन्होंने 2015 के नियमों की वैधता का मुद्दा उठाया।चूंकि उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, नियमों को चुनौती देना छोड़ दिया गया था,

इसलिए मामलों का निपटारा एक सहमत आदेश के संदर्भ में किया गया था।2015 का एस.एल पी विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 26871 जिसका शीर्षक था 'दीपक कुंडू और अन्य बनाम। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल और अन्य 'दायर किए गए थे जिसमें रोहतक और पानीपत बार एसोसिएशनों द्वारा शिकायत की गई थी कि वे उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, फिर भी उन्हें बाध्य करने वाला आदेश पारित किया गया था।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों बार एसोसिएशनों को सहमत आदेश पारित करने से पहले नहीं सुना गया था, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और सभी प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।कुछ अन्य एसएलपी को भी इसी तरह निपटाया गया था।

(4) 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5232 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य बार काउंसिल के पास 1961 के अधिनियम की खंड 6 या 15 या किसी अन्य प्रावधान के तहत बार एसोसिएशनों के चुनाव के संचालन को विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है जो वकीलों के निजी संघ हैं जो अपने स्वयं के उपनियमों द्वारा विनियमित हैं। तदनुसार उनका तर्क है कि 2015 के नियम 1961 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत हैं और इस प्रकार बिना किसी वैधानिक आधार के होने के कारण बार एसोसिएशनों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि ये नियम याचिकाकर्ताओं के संघ बनाने के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत दी गई है।

(5) एल. डी. इसके बाद वकील ने नियम बनाने में प्रक्रियात्मक भंग के बारे में तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि 'अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न समितियों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित नियमों' के नियम 52 (एच) के अनुसार, नियमों का मसौदा तैयार करने का कार्य 'नियम मसौदा समिति' को सौंपा गया है, जिसे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के समक्ष मसौदा प्रस्तुत करना है।यह तर्क दिया गया है कि विवादित नियमों का मसौदा राकेश पूनिया बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया

और अन्य द्वारा तैयार नहीं किया गया था। समिति और न ही मसौदा नियमों को मंजूरी के लिए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के समक्ष रखा गया था।बल्कि नियमों को राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए बिना अनुमोदन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया था।इस प्रकार उक्त नियमों के नियम 52 (एच) का उल्लंघन किया गया है।

(6) श्री हरजोत सिंह हरिके अधिवक्ता, जिन्होंने पहले 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.6047 दायर किया था, जिसमें 2015 के नियमों को कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गई थी, को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी।उन्होंने नियम बनाने के लिए बार काउंसिल की शक्ति पर विवाद नहीं किया और वास्तव में, तर्क दिया कि नियम बनाना वांछनीय है।

(7) एल. डी. पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के वकील ने तर्क दिया कि नियम बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल की शक्ति का स्रोत अधिवक्ता अधिनियम की खंड 15 के साथ पठित खंड 6 (डीडी), 6 (एच) और 6 (आई) में निहित है। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (संक्षेप में "2001 अधिनियम") की खंड 16,17 और 18 पर भी भरोसा किया।उन्होंने आगे कहा कि इन नियमों को तैयार करने में राज्य बार काउंसिल का उद्देश्य केवल बार एसोसिएशनों के चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और किसी भी नियंत्रण का प्रयोग नहीं करना या अन्यथा उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना है और वे पहले की तरह पूरी तरह से स्वायत्तता का आनंद लेते रहेंगे।उन्होंने कहा कि 1961 के अधिनियम की खंड 15 (3) के संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार, 2015 के नियमों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 02.05.2015 पर आयोजित अपनी बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया है और इस प्रकार, वे कानूनी और वैध हैं।

(8) रिलायंस को उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर रखा गया था। **P.K.Dash,** अधिवक्ता और कंपनी बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और

अन्य 1 यह तर्क देना कि बार एसोसिएशनों को विशुद्ध रूप से निजी संघों के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन उनका मुख्य रूप से सार्वजनिक चरित्र है क्योंकि

उनके कार्य, कई मामलों में, अदालत के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(9) इस बात से इनकार करते हुए कि नियम बनाने में कोई प्रक्रियात्मक भंग हुआ था, एल. डी. वकील ने हमें पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित नियम तैयार करने के विषय पर अध्यक्ष नियम मसौदा समिति को संबोधित 2.2.2015 का पत्र भेजा।पत्र के साथ उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें तुरंत नियम बनाने का अनुरोध किया गया था।उन्होंने अध्यक्ष नियम मसौदा समिति से राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष को दिनांक 10.2.2015 पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने नियमों का मसौदा भेजा था।

1 आकाशवाणी 2016 दिल्ली 135 88

इसके बाद पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा 01.03.2015 को हुई बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 7 की प्रति का उल्लेख किया गया, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि नए बनाए गए नियमों को 1961 के अधिनियम की धारा 15 (3) के तहत अनुमोदन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाए। नियमों को 5.3.2015 पर अनुमोदन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया था।बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2.5.2015 पर आयोजित जनरल हाउस की बैठक में नियमों को मंजूरी दी।इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि नियमों का मसौदा नियम मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा विचार और अनुमोदन किया गया और बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया, और इस प्रकार आदेश में हैं।

(10) हमने एल. डी. सुना है। पार्टियों के वकील ने रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

(11) चूंकि इन याचिकाओं में मुख्य मुद्दा नियमों को तैयार करने के लिए राज्य बार काउंसिल की क्षमता है, इसलिए हमें पहले के मुकदमे का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जो नियमों को तैयार करने के लिए तत्काल उत्प्रेरक प्रदान

करता है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा नियमों को तैयार करने के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया था 2014 के एल पी ए No.1427 जैसा कि सीएम-988-989-एलपीए-2015 में दिंनाक 25.03.15 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया था। **2014** मोहिंदर सिंह चौहान बनाम बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड अन्र।

(12) प्रतिवादी बार काउंसिल की ओर से कहा गया है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब और हरियाणा के सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों/सचिवों/पदाधिकारियों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और उनके प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उक्त नियम बनाए गए थे।

(13) नियमों के उद्देश्य और उद्देश्य नियम 1 में निम्नानुसार बताए गए हैं:

"लक्ष्य और उद्देश्य:-

i) एकरूपता लाने के लिए, सभी बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के चुनावों से संबंधित पारदर्शिता पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ii) विभिन्न बार एसोसिएशनों द्वारा बनाए गए जटिलता उप कानूनों से बचने के लिए जो बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों में शुद्धता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं।"

संबंधित स्थिति प्रावधान

(14) इस मुद्दे पर आदेश लेने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों और इसकी सामान्य योजना और उद्देश्यों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 भी प्रासंगिक होगा, जो कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, जिन्होंने अधिनियम की अनुसूची II में उल्लिखित अपने स्वयं के अधिवक्ता कल्याण अधिनियम बनाए हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए कुछ नियमों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ जिसमें न्यायालय द्वारा संबद्ध विधिज्ञ संघों द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यात्मक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, भी सहायक होगा।

((i) अधिवक्ता अधिनियम**, 1961**

(15) जैसा कि 1961 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है, यह कानूनी व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है।

अधिनियमन का उद्देश्य और कारण उसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में परिलक्षित होता है, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"यह विधेयक न्यायिक प्रशासन में सुधार के विषय पर विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1953 में की गई अखिल भारतीय बार समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करता है, जहां तक बार और कानूनी शिक्षा से संबंधित सिफारिशें हैं।

2. विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं -

(1) एक अखिल भारतीय बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची की स्थापना, और देश के किसी भी हिस्से में और सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता करने का अधिकार होगा ।

(2) अधिवक्ता के रूप में जाने जाने वाले कानूनी व्यवसायियों के एकल वर्ग में बार का एकीकरण;

(3) अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए एक समान योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन;

(4) योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं में अधिवक्ताओं का विभाजन;

(5) स्वायत्त अधिवक्ता परिषदों का निर्माण, पूरे भारत के लिए एक और प्रत्येक राज्य के लिए एक।

3. अखिल भारतीय बार समिति और विधि आयोग की सिफारिशों के बाद, विधेयक उस ओर से उपयुक्त प्रावधान करके कलकत्ता और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अब प्रचलित दोहरी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली के निरंतर अस्तित्व को मान्यता देता है।हालाँकि, यह दोनों उच्च न्यायालयों के लिए होगा, यदि वे चाहते हैं, तो इस प्रणाली को किसी भी समय बंद कर दें।

4. यह विधेयक, एक व्यापक उपाय होने के नाते, भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 और इस विषय पर अन्य सभी कानूनों को निरस्त करता है।

5. खंडों पर टिप्पणियाँ, जहाँ भी आवश्यक हो, विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करती हैं।"

(16) जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यू. पी. की बार काउंसिल बनाम यू. पी. 2 के मामले में माना किया है, 1961 का अधिनियम, अपने सार और सार में, अधिवक्ताओं की योग्यता, नामांकन, वकालत करने के अधिकार और अनुशासन से संबंधित एक अधिनियम है।

(17) मूल रूप से अधिनियमित 1961 के अधिनियम में बार एसोसिएशन या एडवोकेट्स एसोसिएशन का कोई संदर्भ या उल्लेख नहीं था।तब से 1961 के अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अधिनियम का दायरा बढ़ाया गया है और बार एसोसिएशनों को वैधानिक मान्यता दी गई है।बाद के अधिनियमों और नियमों ने भी बार एसोसिएशनों के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की है।

(18) राज्य बार परिषदों के कार्य 1961 के अधिनियम की खंड 6 में निर्धारित किए गए हैं, जिसे आज तक संशोधित किया गया हैः

"6. राज्य बार परिषदों के कार्य-

(1) एक राज्य बार काउंसिल के काम होगे -

(a) अपनी भूमिका में व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में स्वीकार करना।

(b) इस तरह के रोल को तैयार करना और बनाए रखना।

(c) दुराचार के मामलों पर विचार करना और उनका निर्धारण करना।

अपने रोल पर अधिवक्ताओं के खिलाफ

((d) के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना।

इसके रोल पर अधिवक्ता

[(dd) इस 2 ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 331 की उप-खंड (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से बार संघों के विकास को बढ़ावा देना।

खंड 7 की उप-खंड (2) की खंड और खंड (a);]

(e) कानून सुधार को बढ़ावा देना और समर्थन करना।

[(ee) प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा कानूनी विषयों पर सेमिनार आयोजित करना और वार्ता आयोजित करना और कानूनी हित की पत्रिकाओं और पत्रों को प्रकाशित करना।

(e.e.e.) गरीबों को निर्धारित तरीके से कानूनी सहायता का आयोजन करना]

(f) अपने सदस्यों के चुनाव के लिए व्यवस्था करने के लिए बार काउंसिल

(g) के धन का प्रबंधन और निवेश करना।

[(gg) धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (I) के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों का दौरा करना और निरीक्षण करना;]

(i)इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य सभी कार्यों को पूरा करना

((i) निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना।उपरोक्त कार्य

[(2) राज्य बार परिषद निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्धारित तरीके से एक या अधिक निधियों का गठन कर सकती है -

(a) कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देना।

निर्धन, विकलांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए;

(b) नियमों के अनुसार कानूनी सहायता या सलाह देना।

इस संबंध में किया गया;

(c) विधि पुस्तकालयों की स्थापना]।

(3) राज्य बार काउंसिल उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान, दान, उपहार या लाभ प्राप्त कर सकती है जो उस उप-धारा के तहत गठित उपयुक्त निधि या निधियों में जमा किया जाएगा।]

(19) मूल रूप से खंड 6 में राज्य बार काउंसिल के कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:-

"6. राज्य बार परिषद के कार्य।-

(1) के कार्य एक राज्य बार काउंसिल होगी -

(a) अपनी सूची में अधिवक्ताओं के रूप में व्यक्तियों को शामिल करना;

(b) ऐसी सूची तैयार करना और उसका रखरखाव करना;

(c) अपनी भूमिका में अधिवक्ताओं के खिलाफ कदाचार के मामलों पर विचार करना और उनका निर्धारण करना;

(d) अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना;

(e) कानून सुधार को बढ़ावा देना और समर्थन करना;

(f) बार काउंसिल की निधियों का प्रबंधन और निवेश करना;

(g) इसके सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करना;

(h) इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का पालन करना।

((i) उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना।

(2) एक राज्य बार काउंसिल गरीब या विकलांग अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से निर्धारित तरीके से एक कोष का गठन कर सकती है।"

वर्ष 1973 और 1993 में खंड 6 में संशोधन किए गए, जिसका प्रभाव राज्य बार परिषदों के कार्यों को बढ़ाने पर पड़ा।खंड 6 (1) (e. e.) को अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा सेमिनार आयोजित करने और प्रख्यात न्यायविदों द्वारा कानूनी विषयों पर वार्ता आयोजित करने और कानूनी हित की पत्रिकाओं और पत्रों को प्रकाशित करने के लिए जोड़ा गया था।उसी संशोधन अधिनियम द्वारा खंड 6 (1) (e. e. e.) को भी जोड़ा गया था, जिससे राज्य बार काउंसिलों को गरीबों को कानूनी सहायता का आयोजन करने में मदद मिली।पूर्ववर्ती उप-खंड (2) के स्थान पर एक नई उप-खंड को प्रतिस्थापित करके उप-खंड (2) का दायरा बढ़ाया गया था।प्रतिस्थापित उप-धारा के अनुसार, एक राज्य बार काउंसिल गरीब, विकलांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कानूनी सहायता या सलाह देने के उद्देश्य से एक या अधिक निधियों का गठन कर सकती है। एक नई उप-धारा (3) जोड़ी गई। राज्य बार काउंसिल को उप-धारा (2)

में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान, दान, उपहार या लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

(20) अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य बार परिषदों के कार्यों को और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया।

(21) जैसा कि खंड 6 (1) (डी. डी.) में प्रावधान किया गया है, जिस पर एल. डी. द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है। प्रतिवादी के लिए वकील, यह बार काउंसिल का कार्य है कि बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा दे। खंड 6 की उप-खंड (2) के खंड (ए) और खंड 7 की उप-खंड (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का उद्देश्य।खंड 6 (2) (सी) जो कानून पुस्तकालयों की स्थापना के उद्देश्य से धन के गठन को सक्षम बनाती है, 1993 में भी जोड़ी गई थी।

(22) उपरोक्त संशोधन के पूर्ण महत्व को समझने के लिए, अधिवक्ताओं के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (संशोधन) आदेश 1993 का संदर्भ सहायक होगाः

" 1993 का अधिनियम 70 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

भारतीय बार परिषद और कुछ अन्य निकायों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के प्रशासन में प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय बार परिषद और राज्य बार परिषदों को कानूनी पेशे की बेहतरी के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक पाया गया है।

1. विधेयक अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ इसका भी प्रस्ताव है।-

(i) अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों पर विश्वविद्यालयों का दौरा करने और निरीक्षण करने और कानून पुस्तकालयों की स्थापना के लिए धन का गठन करने के लिए राज्य बार काउंसिलों को सशक्त बनाना।

(ii) परिणामी व्यवस्था करने के लिए निर्धारित अवधि के साथ चुनाव न होने की स्थिति में राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों की सदस्यता की स्वतः समाप्ति का प्रावधान करता है;

(iii) भारतीय बार परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषदों को अपने-अपने मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर बैठक करने में सक्षम बनाना;

((iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वर्तमान में देय शुल्क में बाधा डाले बिना नामांकन शुल्क को दो सौ पचास रुपये से बढ़ाकर सात सौ पचास रुपये कर दिया जाए।

(v) राज्य बार काउंसिलों को किसी व्यक्ति को राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश नहीं देने का अधिकार देता है यदि उसे राज्य 94 के तहत किसी भी रोजगार या पद से बर्खास्त या हटा दिया गया है।

नैतिक अधमता से जुड़े आरोप पर।

(vi) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उन व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है जो उस न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने के हकदार होंगे।

(2) विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।"

स्पष्ट रूप से, 1993 के संशोधन के मुख्य उद्देश्यों में से एक अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य बार काउंसिलों को सशक्त बनाना था।इसी उद्देश्य के लिए खंड 6 (1) (डी. डी.) जोड़ी गई थी।माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम बी. डी. कौशिक, (2011) 13 एस. सी. सी. 774 में इस पहलू का उल्लेख करते हुए कहा कि 1961 के अधिनियम के तहत राज्य बार काउंसिलों के मुख्य कार्यों में से एक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देना है।न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"23. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 विभिन्न राज्य बार परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है, जिनका एक मुख्य कार्य अधिवक्ताओं को अपनी सूची में शामिल करना और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से विधिज्ञ संघों के विकास को बढ़ावा देना है।यह बार काउंसिलों को अपने स्वयं के नियम बनाने में सक्षम बनाता है। अधिवक्ता अधिनियम की खंड 17 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं की सूची तैयार करेगी और उसका रखरखाव करेगी।खंड 17 (4) में आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य बार काउंसिल की सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।"

(23) 1961 के अधिनियम की धारा 15 भारतीय बार परिषद और राज्य बार परिषद दोनों को खंड 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। आम तौर पर बार काउंसिलों को खंड II के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने के अलावा, जिसमें धारा 3 से 15 शामिल हैं, यह विशिष्ट उद्देश्यों को सूचीबद्ध करता है जिनके लिए नियम प्रदान कर सकते हैं।खंड 15 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

"15. नियम बनाने की शक्ति।— **(1)** एक बार काउंसिल इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -

[(a) गुप्त मतपत्र द्वारा बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव, जिसमें वे शर्तें भी शामिल हैं जिनके अधीन व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, भारत की मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन और चुनाव के परिणाम प्रकाशित करने का तरीका;]

(b) [* * *]

[(c) बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का तरीका;]

(d) बार काउंसिल [या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए] चुनाव की वैधता के बारे में संदेह और विवाद का अंतिम निर्णय किया जाएगा;

(e) [* * *]

(f) बार काउंसिल में आकस्मिक रिक्तियों को भरना;

(g) बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य;

[(ga) धारा 6 खंड (2) और धारा 7 खंड (2) में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता देने या कानूनी सहायता या सलाह देने के उद्देश्य से बार काउंसिल द्वारा एक या अधिक निधियों का गठन;

(g.b. गरीबों को कानूनी सहायता और सलाह का संगठन, उस उद्देश्य के लिए समितियों और उप-समितियों का गठन और कार्य और उन कार्यवाहियों का विवरण जिनके संबंध में कानूनी सहायता या सलाह दी जा सकती है।

(h) बार काउंसिल की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, उसमें कार्य संचालन और कोरम गठित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या; (i) बार काउंसिल की किसी समिति का गठन और कार्य और ऐसी किसी समिति के सदस्यों का कार्यकाल;

(j) बैठकें बुलाना और आयोजित करना, ऐसी किसी समिति का कार्य संचालन और कोरम गठित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(k) सचिव, लेखाकार और बार काउंसिल के अन्य कर्मचारियों की योग्यता और सेवा की शर्तें;

(l) लेखा पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का रखरखाव

बार काउंसिल द्वारा;

(m) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और बार काउंसिल के खातों का ऑडिट;

(n) बार काउंसिल की निधियों का प्रबंधन और निवेश।

(3) राज्य बार परिषद द्वारा इस खंड के तहत बनाए गए कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि उन्हें भारतीय बार परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।"

((ii) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम**, 2001**

(24) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 अधिवक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और गरीब या विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।इस अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य बार परिषदों

द्वारा मान्यता प्राप्त बार संघों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वास्तव में केंद्रीय भूमिका की परिकल्पना की गई थी।

(25) इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का संदर्भ आवश्यक होगाः

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण।- सामाजिक सुरक्षा

कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता और गरीब या विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का रूप लंबे समय से कानूनी बिरादरी के लिए चिंता का विषय रहा है।खंड 6 की उप-खंड (2) का खंड (ए) और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 7 की उप-खंड (2) का खंड (ए), राज्य विधिज्ञ परिषदों के साथ-साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ, 'निर्धनों, विकलांगों या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय सहायता देने' के उद्देश्य द्वारा अपने नियमों के माध्यम द्वारा

एक या अधिक निधियों का गठन करने की शक्तियां प्रदान करता है।खंड 6 की उप-खंड (3) और अधिवक्ता अधिनियम की खंड 7 की उप-खंड (3) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ-साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद उक्त उद्देश्य के लिए अनुदान, दान, उपहार या लाभ प्राप्त कर सकती है जो उक्त खंडओं की उप-खंड (2) के तहत गठित उचित निधि या निधियों में जमा किया जाएगा।तदनुसार कुछ राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।अधिकांश राज्यों ने इस विषय पर कानून बनाए हैं। हालाँकि, न तो कोई एकरूपता है और न ही उक्त प्रावधानों को माना जाता है। पर्याप्त है। इसके अलावा, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 वकालतनामा पर किसी भी कल्याणकारी निधि की मुहर लगाने को अधिकृत नहीं करता है।इसलिए, उपयुक्त सरकार द्वारा "अधिवक्ता कल्याण कोष" के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए एक केंद्रीय कानून लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिनके पास इस विषय पर अपने स्वयं के अधिनियम नहीं हैं।यह कोष, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, राज्य बार काउंसिल द्वारा किए गए योगदान, भारतीय बार काउंसिल, अधिवक्ता संघों, अन्य संघों या संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी स्वैच्छिक दान या योगदान, उपयुक्त सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अनुदान, "अधिवक्ता कल्याण निधि टिकटों" की बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई राशि से बना होगा।

2. सभी वकालत करने वाले अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक सदस्यता के भुगतान पर निधि के सदस्य बन जाएंगे।निधि उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित होगी और उसके पास होगी और उसके द्वारा लागू की जाएगी।इस निधि का उपयोग, अन्य बातों के साथ साथ , किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के मामले में निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान देने, प्रैक्टिस बंद करने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने और किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में, उसके नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को, सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, पुस्तकों की खरीद और अधिवक्ताओं के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा।कोष में उपार्जित आय को आयकर से छूट दी जाएगी।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।"

(26) इस अधिनियम के तहत लाभों का दावा करने के लिए अधिवक्ता का नाम राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए राज्य सूची में दर्ज किया जाना चाहिए और वह राज्य बार एसोसिएशन या राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य भी होना चाहिए।वास्तव में, अधिनियम की खंड 2 (ए) में 'अधिवक्ता' की परिभाषा में इस शर्त को शामिल किया गया है।अधिनियम की खंड 3 में 'अधिवक्ता कल्याण कोष' के गठन की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि जमा की जाएगी और जो अधिनियम के तहत परिकल्पित लाभों के वितरण के लिए कोष बनाएगी। अधिनियम का अध्याय-IV राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं के संघ की मान्यता से संबंधित है। खंड 16 के अनुसार, अधिनियम के प्रारंभ से पहले पंजीकृत अधिवक्ताओं के किसी भी संघ को राज्य बार काउंसिल को मान्यता के लिए आवेदन करना आवश्यक है।इसी तरह, इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं के किसी भी संघ के लिए की आवश्यकता है। राज्य बार काउंसिल के पंजीकरण के तीन महीने के भीतर मान्यता के लिए आवेदन करें।खंड 16 (3) के अनुसार मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संघ के नियमों और उप-कानूनों की एक प्रति, संघ के पदाधिकारियों के नाम और पते; संघ के सदस्यों की एक सूची जिसमें नाम, पता, आयु, नामांकन संख्या, नामांकन की तारीख और अभ्यास का सामान्य स्थान होना आवश्यक है।खंड 16 (4) के अनुसार, राज्य बार काउंसिल ऐसी जांच करने के बाद एसोसिएशन को मान्यता दे सकती है जो उसे आवश्यक लगे।किसी संगठन की मान्यता के संबंध में बार काउंसिल का निर्णय अंतिम

बना दिया गया है।इस अधिनियम की खंड 17 प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ को हर साल 15 अप्रैल को या उससे पहले राज्य बार काउंसिल को अपने सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है।खंड 17 (2) के अनुसार, ऐसे प्रत्येक संघ को राज्य बार काउंसिल को सदस्यता में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश और पुनः प्रवेश, मृत्यु या अभ्यास की समाप्ति या ऐसी घटना के तीस दिनों के भीतर अभ्यास का स्वैच्छिक निलंबन शामिल है।खंड 17 (2) (सी) के अनुसार प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ को राज्य बार काउंसिल को ऐसे अन्य मामलों के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो समय-समय पर राज्य बार

काउंसिल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।खंड 18 (1) के अनुसार, किसी राज्य में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले अधिवक्ता करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता और जो राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य है (जो क्रमशः खंड 2 (पी) और 2 (क्यू) में उनकी परिभाषा के अनुसार, खंड 16 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त एक संघ है), अधिनियम के प्रारंभ के छह महीने के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए न्यासी समिति में आवेदन करेगा।इसी तरह, अधिनियम के प्रारंभ के बाद राज्य बार काउंसिल की सूची में भर्ती होने वाले अधिवक्ताओं और राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ के सदस्य होने के नाते, उन्हें अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के छह महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

(27) इस प्रकार, 2001 के अधिनियम की योजना के अनुसार, एक अधिवक्ता के लिए राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का सदस्य होना अधिवक्ता कल्याण कोष का सदस्य बनने के लिए एक पूर्व शर्त है।

(28) 2001 के अधिनियम की खंड 26 राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि टिकटों के मुद्रण और वितरण से संबंधित है।उप-धारा (1) के अनुसार, उपयुक्त सरकार को राज्य बार काउंसिल के अनुरोध पर 'अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट' छापना आवश्यक है, जिसकी अभिरक्षा परिषद और अन्य की उप-धारा (3) के अनुसार है। खंड 26 राज्य बार काउंसिल के पास होगी।खंड 26 की उप-खंड (4) के अनुसार, राज्य बार काउंसिल राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघों के माध्यम द्वारा टिकटों के वितरण और बिक्री को नियंत्रित करेगी।खंड 26 की उप-खंड (5) राज्य बार काउंसिल, राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ से डाक टिकटों का उचित लेखा इस

तरह से रखने की अपेक्षा करती है जो निर्धारित किया जाए।खंड 26 (6) के अनुसार राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ आकस्मिक शुल्क के लिए ऐसे मूल्य के 10 प्रतिशत तक कम मूल्य का भुगतान करने के बाद राज्य बार काउंसिल से टिकट खरीदेंगे। खंड 27 प्रत्येक अधिवक्ता से रुपये के मूल्य की मुहर लगाने की अपेक्षा करती है। 5/- जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में दायर प्रत्येक वकालतनामा पर और Rs.10-न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर प्रत्येक

वकालतनामा पर।इस आवश्यकता का कोई भी उल्लंघन अधिवक्ता को निधि के लाभों से वंचित कर देगा।

(29) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को इस अधिनियम की खंड 35 के संदर्भ में प्रदान की गई है। खंड 36 के अनुसार, उपयुक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम भी बना सकती है, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के साथ असंगत नहीं हैं।

(30) 2001 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान जो इस अधिनियम की योजना में राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशनों की महत्वपूर्ण स्थिति को उजागर करते हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो-
(a) "अधिवक्ता" से ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की खंड 17 के तहत राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा तैयार और बनाए रखी गई राज्य सूची में दर्ज किया गया है और जो राज्य अधिवक्ता संघ या राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य है;

(p) "राज्य अधिवक्ता संघ" से खंड 16 के तहत उस राज्य की बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य में अधिवक्ताओं का एक संघ है;

(q) "राज्य बार एसोसिएशन" का अर्थ है खंड 16 के तहत उस राज्य की बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ताओं का एक संघ;

अध्याय II

अधिवक्ताओं के कल्याण निधि का गठन

3. अधिवक्ता कल्याण कोष।— (1) उपयुक्त सरकार एक कोष का गठन करेगी जिसे "अधिवक्ता कल्याण कोष" कहा जाएगा।संबंधित राज्यों की बार काउंसिलों की सूची में भर्ती अधिवक्ताओं के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों की बार काउंसिलों की सूची में भर्ती अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन किया जाना है।

(2) कोष में जमा किया जाएगा -

(a) खंड 15 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा भुगतान की गई सभी राशियाँ;

(b) राज्य बार काउंसिल द्वारा किया गया कोई अन्य योगदान;

(c) भारतीय बार काउंसिल, किसी राज्य बार एसोसिएशन, किसी राज्य अधिवक्ता संघ या अन्य संघ या संस्थान, या किसी अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा कोष में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या योगदान;

(d) कोई अनुदान जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस ओर से किए गए उचित विनियोग के बाद कोष में दिया जा सकता है।

(e) खंड 12 के तहत उधार ली गई कोई भी राशि;

(f) खंड 18 के तहत एकत्र की गई सभी राशि;

(g) किसी भी समूह बीमा पॉलिसी के तहत कोष के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त सभी राशि;

(h) कोष के सदस्यों की समूह बीमा पॉलिसियों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश या धनवापसी;

((i) निधि के किसी भी भाग से किए गए किसी भी निवेश पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य लाभ;

(j) खंड 26 के तहत टिकटों की बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई सभी राशियाँ।

(3) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों का भुगतान ऐसी अभिकरणों को ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

अध्याय IV

अधिवक्ताओं के किसी भी संगठन की मान्यता

16. राज्य बार परिषद द्वारा अधिवक्ताओं के किसी भी संघ की मान्यता।—

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले एक संघ के रूप में पंजीकृत किसी भी नाम से जाना जाने वाला अधिवक्ताओं का कोई भी संघ, इस संबंध में राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पहले, राज्य बार काउंसिल को मान्यता के लिए ऐसे प्रपत्र में आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाए।

(2) अधिवक्ताओं का कोई भी संघ, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद एक संघ के रूप में पंजीकृत है, एक संघ के रूप में अपने पंजीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर, राज्य बार काउंसिल को मान्यता के लिए ऐसे प्रपत्र में आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाए।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ होगा -

(a) संघ के नियमों या उपनियमों की एक प्रति;

(b) एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम और पते;

(c) एसोसिएशन के सदस्यों की एक सूची जिसमें नाम, पता, आयु, नामांकन संख्या और राज्य बार काउंसिल में नामांकन की तारीख और प्रत्येक सदस्य का अभ्यास का सामान्य स्थान शामिल है।

(4) राज्य बार काउंसिल, ऐसी जांच के बाद, जो वह आवश्यक समझे, एसोसिएशन को मान्यता दे सकती है और ऐसे प्रपत्र में मान्यता का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जो निर्धारित किया जाए।

(5) उप-धारा (4) के तहत किसी संघ की मान्यता के संबंध में किसी भी मामले पर राज्य बार काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण।—इस खंड में, "पंजीकृत" का अर्थ है सोसायटी पंजीकरण 102 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत माना जाना।

अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या उस समय लागू कोई अन्य कानून।

17. राज्य अधिवक्ता संघों और राज्य अधिवक्ता संघों के कर्तव्य।—

(1) प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पहले, राज्य बार काउंसिल को उस वर्ष के 31 मार्च को अपने सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ राज्य बार काउंसिल को सूचित करेंगे -

(a) इस तरह के परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर प्रवेश और पुनः प्रवेश सहित सदस्यता में कोई परिवर्तन;

(b) उसके होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसके किसी भी सदस्य की मृत्यु या अभ्यास की अन्य समाप्ति या अभ्यास का स्वैच्छिक निलंबन;

(c) ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर राज्य बार काउंसिल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

पाँचवाँ अध्याय

अधिवक्ताओं के कल्याण निधि की सदस्यता और भुगतान

18. कोष में सदस्यता।— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किसी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में अधिवक्ता करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता और उस राज्य में राज्य अधिवक्ता संघ या राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य होने के नाते, इस अधिनियम के प्रारंभ के छह महीने के भीतर, निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, -

(a) इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, राज्य बार काउंसिल की सूची में एक अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया गया;

(b) किसी राज्य में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कार्य करने वाला और उस राज्य में राज्य अधिवक्ता संघ या राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य होने के नाते, एक अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के छह महीने के भीतर, न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए।

(3) उप-खंड (1) या उप-खंड (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर न्यासी समिति ऐसी जांच करेगी जो वह उचित समझे और या तो आवेदक को निधि में भर्ती करेगी या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर देगी:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) प्रत्येक आवेदक न्यासी समिति के खाते में आवेदन के साथ दो सौ रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा।

(5) प्रत्येक अधिवक्ता कोष का सदस्य होने के नाते, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले कोष में पचास रुपये की वार्षिक सदस्यता का भुगतान करेगा:

बशर्ते कि प्रत्येक अधिवक्ता जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आवेदन करता है, निधि का सदस्य बनने के तीन महीने के भीतर अपनी पहली वार्षिक सदस्यता का भुगतान करेगाः

बशर्ते कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता एक हजार रुपये की वार्षिक सदस्यता का भुगतान करेगा।

(6) कोष का कोई भी सदस्य, जो उस वर्ष के 31 मार्च से पहले किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक सदस्यता का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे कोष की सदस्यता से हटा दिया जाएगा।

(7) उप-धारा (6) के तहत निधि की सदस्यता से हटाए गए निधि के किसी सदस्य को इस तरह के निष्कासन की तारीख से छह महीने के भीतर दस रुपये के पुनः प्रवेश शुल्क के साथ अवशिष्ट राशि के भुगतान पर निधि में फिर से प्रवेश दिया जा सकता है।

(8) कोष का प्रत्येक सदस्य, कोष में सदस्यता में प्रवेश के समय, अपने एक या अधिक आश्रितों को उनकी मृत्यु की स्थिति में, इस अधिनियम के तहत सदस्य को देय किसी भी राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए नामांकन करेगा।

(9) यदि निधि का कोई सदस्य उप-धारा (8) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय राशि या हिस्से को निर्दिष्ट करेगा।

(10) कोष का कोई सदस्य किसी भी समय न्यासी समिति को लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता है।

(11) कोष का प्रत्येक सदस्य, जो उप-धारा (10) के तहत अपना नामांकन रद्द करता है, पाँच रुपये के पंजीकरण शुल्क के साथ एक नया नामांकन करेगा।

(12) कोष का प्रत्येक सदस्य, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की खंड 26 ए के तहत राज्य सूची से हटा दिया गया है, या जो स्वेच्छा से अभ्यास को निलंबित करता है, ऐसे निष्कासन या निलंबन के पंद्रह दिनों के भीतर न्यासी समिति को इस तरह के निष्कासन या निलंबन की सूचना देगा और यदि कोष का कोई सदस्य बिना पर्याप्त कारण के ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यासी समिति ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो निर्धारित किए जाएं, इस अधिनियम के तहत उस सदस्य को देय राशि को कम कर सकती है। किसी राज्य में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में अधिवक्ता करने वाले और उस राज्य में राज्य बार एसोसिएशन या राज्य

अधिवक्ता संघ के सदस्य होने के नाते प्रत्येक अधिवक्ता को कोष के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए न्यासी समिति में आवेदन करना होता है।प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ दो सौ रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।कोष के सदस्य के रूप में भर्ती होने वाले प्रत्येक अधिवक्ता को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले कोष में पचास रुपये की वार्षिक सदस्यता का भुगतान करना आवश्यक है।उस वर्ष के 31 मार्च से

पहले वार्षिक सदस्यता का भुगतान करने में विफलता, उसे निधि की सदस्यता से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

अध्याय VI

स्टैम्प की छपाई, वितरण और रद्द करना

26. राज्य बार परिषद द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि डाक टिकटों का मुद्रण और वितरण।— **(1)** उपयुक्त

सरकार, इस संबंध में राज्य बार काउंसिल द्वारा किए गए अनुरोध पर, पांच रुपये या ऐसे अन्य मूल्य के अधिवक्ता कल्याण निधि डाक टिकटों को मुद्रित और वितरित करेगी, जो उसमें "अधिवक्ता कल्याण निधि डाक टिकट" अंकित करके निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक डाक टिकट का होगा।

आकार 2.54 से. मी. से 5.8 से. मी. तक और अधिवक्ताओं को बेचा गया।

(3) डाक टिकटों की अभिरक्षा राज्य बार काउंसिल के पास होगी।

(4) राज्य बार काउंसिल राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघों के माध्यम द्वारा टिकटों के वितरण और बिक्री को नियंत्रित करेगी।

(5) राज्य बार काउंसिल, राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ डाक टिकटों का उचित लेखा-जोखा ऐसे प्रपत्र और तरीके से रखेंगे जो निर्धारित किया जाए।

(6) राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ राज्य बार काउंसिल से डाक टिकटों को उनके मूल्य में दस प्रतिशत की कमी के भुगतान के बाद खरीदेंगे।आनुषंगिक खर्चों के लिए ऐसा मूल्य।"

(iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस **(**वेरिफिकेशन**)** नियम**, 2015**

(31) बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1961 के अधिनियम की खंड 49 (1) (ए. जी.), 49 (ए. एच.) 49 (आई.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम, 2015 (संक्षेप में 'सत्यापन नियम') बनाए हैं।इन नियमों को बार काउंसिल/बार एसोसिएशन के चुनावों में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है।यह आवश्यक था क्योंकि हाल के दिनों में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को चुनावों में धांधली के मामलों और फर्जी मतदान के आरोपों का सामना करना पड़ा था।यह देखा गया कि राज्य बार परिषदों और/या देश के अधिकांश बार संघों के पास उन अधिवक्ताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं था जिनकी नामांकन के बाद मृत्यु हो गई या जो अन्य नौकरियों, व्यवसाय या व्यवसायों में शामिल हो गए।ऐसे गैर-अधिवक्ता राज्य विधानों के साथ-साथ विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय बार परिषद द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में भी कामयाब रहे।

(32) इन नियमों को तैयार करने के उद्देश्यों को इन नियमों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में पूरी तरह से समझाया गया है जो निम्नानुसार हैः

"कानूनी पेशा एक सम्मानित पेशा है और लोगों के नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।एक स्वतंत्र और निडर बार एक सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है।बार, जो बाहरी शक्तियों के हेरफेर और प्रभाव के अधीन है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली और सम्मानित क्यों न हों, कानूनी पेशे या कानून के शासन के साथ न्यायाधीश नहीं कर सकता है। पीठ और बार रथ के दो पहिये हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता है।अफसोस की बात है कि यह पेशा एक बादल के नीचे गिर गया है।

सभी राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई कि राज्य बार काउंसिल को बिना किसी जानकारी के अधिवक्ताओं के अन्य व्यवसायों/सेवाओं/व्यवसाय में जाने की प्रवृत्ति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।यह प्रवृत्ति समग्र रूप से कानूनी पेशे

को खतरे में डाल रही है।इसने अपनी पवित्रता और मानकों में भी सेंध लगा दी है।इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने कानूनी पेशा छोड़ दिया है या तब से उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे अधिवक्ताओं के नाम राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए "अधिवक्ताओं की सूची" में शामिल किए जाते रहते हैं।यद्यपि अधिवक्ता अधिनियम की खंड 19 के तहत, राज्य बार काउंसिल अधिनियम की खंड 17 के तहत उसके द्वारा तैयार अधिवक्ताओं की सूची की एक प्रति और उसके बाद के परिवर्तनों/परिवर्धनों को भेजने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से किसी भी राज्य बार काउंसिल ने अब तक अधिनियम के इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है।

इन परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि एक निश्चित प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार संघों और अन्य निर्वाचित निकायों का नियंत्रण कानून का अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के हाथों से फिसल रहा है।यह भी अनुभव किया जा रहा है कि एक अधिवक्ता को नामांकन का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, व्यावहारिक रूप से उसके और परिषद के बीच कोई संवादात्मक और निरंतर संपर्क नहीं रहता है। मौजूदा स्थिति के तहत, कानूनी पेशे के मानक में सुधार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/टिप्पणियों पर शुरू की गई अखिल भारतीय बार परीक्षा भी अपने उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रही है।

राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता "प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" (2 साल के लिए वैध) प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठने और इसे पास करने की परवाह किए बिना कानून का अभ्यास कर रहे हैं।

भारत में राज्य विधानों के साथ-साथ विभिन्न राज्य बार काउंसिलों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इसके तहत उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है जिन्होंने पेशा छोड़ दिया है।

विभिन्न न्यायालयों में कानून का अभ्यास करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करने की भी तत्काल आवश्यकता है ताकि अनुभव को उचित महत्व और विश्वसनीयता दी जा सके। इससे पहले कि कोई अधिवक्ता उच्च न्यायालयों में कानून का

अभ्यास कर सके, यह आवश्यक है कि उसे निचले न्यायालयों/विचारण न्यायालयों में वास्तविक न्यायालय के अनुभव से अवगत कराया जाए।इससे बार के दृष्टिकोण से पूरी न्यायिक प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की खंड 22 के तहत विभिन्न राज्य अधिवक्ता परिषदों द्वारा बनाए जा रहे अधिवक्ताओं के रोल पर दर्ज अधिवक्ताओं पर स्थानीय बार एसोसिएशन, राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बेहतर और प्रभावी प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए और वकालत छोड़ने वाले अधिवक्ताओं को बाहर करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 49 (1) (एजी), 49 (एएच) 49 (आई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें निहित अन्य सभी सक्षम और अवशिष्ट शक्तियों द्वारा, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिन्यूअल रूल्स, 2014" शीर्षक से नियम लाए थे।-

लेकिन कुछ स्थानों पर, अधिवक्ताओं ने नवीकरण शब्द के संबंध में आपत्ति जताई, हालांकि वास्तव में यह नामांकन का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पहले से ही किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता के विवरण का आवधिक सत्यापन करना है।इसका उद्देश्य केवल उस स्थान का सत्यापन करना था जहां अधिवक्ता सामान्य रूप से कार्य करता है, बार एसोसिएशन जिसका वह सदस्य है (यदि कोई हो), पता/ईमेल आईडी, नामांकन संख्या/वर्ष, वे संस्थान जहां से अधिवक्ता ने अपनी स्नातक और एल. एल. बी. उत्तीर्ण की है। इसका उद्देश्य देश के सभी अधिवक्ताओं के अभिलेख का रखरखाव है। अधिवक्ता की दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी राज्य बार काउंसिल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।दूसरा उद्देश्य भी था/है को पेश करना। बार काउंसिल/बार एसोसिएशन चुनावों में कुछ चुनावी सुधार, क्योंकि हाल के दिनों में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ने चुनावों में धांधली के मामलों का सामना किया है और फर्जी मतदान के आरोप अब अक्सर हो गए हैं, क्योंकि राज्य बार काउंसिल और/या देश के अधिकांश बार एसोसिएशनों के पास उन अधिवक्ताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिनकी नामांकन के बाद मृत्यु हो गई या जो अन्य नौकरियों, व्यवसाय या व्यवसायों में शामिल हो गए; भारतीय बार काउंसिल ने देश के कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के नियमित होने के

कारण, विस्तृत सत्यापन करने और फिर अधिवक्ता (मतदाता) की हालिया तस्वीरों के साथ एक मतदाता सूची तैयार करने का फैसला किया है।परिषद ने सुप्रीम कोर्ट

बार एसोसिएशन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में ये नियम बनाए हैं।बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही इस उद्देश्य के लिए वेब-पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि देश के सभी अधिवक्ताओं, कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों, कानून के छात्रों, कानून शिक्षकों और सभी बार संघों के विवरण का पूरा विवरण हो सके।उस उद्देश्य के लिए भी विस्तृत जानकारी और फोटो आवश्यक है।इसके अलावा, चूंकि कुछ बार एसोसिएशनों ने Rs.500 की राशि के संबंध में आधारहीन आपत्ति जताई है-अभ्यास शुल्क के रूप में (उनके अनुसार यह एक भारी राशि है); इस Rs.400 के प्रमुख हिस्से (लगभग Rs.400-) का उद्देश्य (2014 के नियमों में) कल्याणकारी योजनाएं (जैसे अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बीमा और बुनियादी ढांचे में सुधार और बार एसोसिएशनों के पुस्तकालय, पेंशन आदि) प्रदान करना था। लेकिन आपत्ति के कारण, अब परिषद ने कल्याण योजनाओं के लिए Rs.400 की इस राशि को सत्यापन की प्रक्रिया शुल्क से अलग करने का संकल्प लिया है।अब केवल Rs.100-वकीलों से प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जाना है और बाकी Rs.400-संबंधित राज्य बार काउंसिल और संबंधित अधिवक्ता के निर्णय के आधार पर वैकल्पिक होगा जो अनिवार्य नहीं होगा।यहां तक कि Rs.100 के इस प्रक्रिया शुल्क से भी, सत्यापन के काम को करने के लिए किए गए खर्च के अलावा, राज्य बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शेष राशि केवल संघों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए खर्च करनी होती है।राज्य विधिज्ञ परिषदों को इस उद्देश्य के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना और बनाए रखना आवश्यक होगा- जिसका हर साल लेखा-परीक्षण किया जाएगा।लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन को भेजी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी पता चला है कि कई नकली (फरज़ी) व्यक्ति (बिना किसी कानून की डिग्री या नामांकन प्रमाण पत्र के) कानूनी प्रैक्टिस में लिप्त हैं और वादियों, अदालतों और अन्य हितधारकों को धोखा दे रहे हैं; और न तो बार एसोसिएशन और न ही संबंधित राज्य बार काउंसिल का ऐसे नकली व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण है।चौंकाने वाली बात यह है कि परिषद के संज्ञान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी या कुछ वोट चाहने वाले जानबूझकर ऐसे लोगों को बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के चुनावों में अपना वोट पाने के उद्देश्य से

अपने एसोसिएशन के सदस्य और मतदाता बनाते हैं।इसी तरह, कई व्यक्ति, किसी भी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बाद, संपत्ति-लेन-देन, अनुबंध या किसी अन्य व्यवसाय, पेशे या नौकरी में शामिल हो जाते हैं और उन्हें कानूनी पेशे से कोई लेना-देना नहीं होता है।इस तरह के "गैर-अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं" का उपयोग कभी-कभी कुछ पदाधिकारी/उम्मीदवारों द्वारा बार एसोसिएशन या बार काउंसिल (केवल अपने वोटों के लिए) के चुनावों के लिए किया जाता है।लेकिन वास्तव में, परिषद ने महसूस किया है कि इस तरह की प्रथा कानूनी पेशे के मानक को कम कर रही है, और इस कुप्रथा को रोकना होगा।

कुछ बार एसोसिएशनों के कुछ पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों ने इन सुधारात्मक कदमों पर अनावश्यक आपत्तियां और विरोध जताया था।इस तरह के विरोध केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए थे।बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी पेशे की गरिमा और मानक बनाए रखना होगा, हमें अदालत-परिसर से नकली लोगों को बाहर करना होगा और हमें "गैर-वकालत करने वाले अधिवक्ताओं" (जो अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में शामिल हैं) की पहचान करनी होगी।हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अधिवक्ता हमारे संघों और बार परिषदों के भाग्य का फैसला करने में शामिल न हों और ऐसे अधिवक्ताओं को तब तक कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त करने या कानूनी पेशे का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे किसी अन्य व्यवसाय, नौकरी या पेशे में हैं। इन्हीं कारणों से परिषद ने ऐसे नकली व्यक्तियों और गैर-वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया है।और परिषद ने भी इसे महसूस किया है । उन अधिवक्ताओं को हतोत्साहित करना आवश्यक है जो अपने वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से नकली और/या गैर-वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को रखने और उनकी रक्षा करने के इरादे से अनावश्यक विरोध प्रदर्शन करते हैं।इसलिए, परिषद ने इन नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का संकल्प लिया है ताकि यदि कोई अधिवक्ता जानबूझकर प्रयास करने में लिप्त पाया जाए -

(i) कानूनी पेशे में काम करने वाले नकली लोगों की रक्षा करें। अवैध रूप से

((ii) "गैर-अभ्यास" की पहचान में कोई बाधा उत्पन्न करना।

अधिवक्ता "और

(iii) प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र, साख, प्रैक्टिस के स्थान और अधिवक्ताओं के विवरण के सत्यापन में कोई आपत्ति पैदा करने के लिए, ऐसे अधिवक्ताओं को आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का कोई भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इन परिस्थितियों में और उपर्युक्त कारणों से, परिषद ने "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिन्यूअल रूल्स 2014" को निरस्त करने का संकल्प लिया है और नए "बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015" को बनाया और पारित किया है और इसे लागू करने का निर्णय लिया है।"

(33) इन नियमों के तहत भी, स्थानीय बार संघों के लिए एक केंद्रीय भूमिका की परिकल्पना की गई है।नियम 6 में प्रावधान है कि एक अधिवक्ता को 1961 के अधिनियम के तहत नामांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है, जहां वह सामान्य रूप से कानून का अभ्यास करता है या कानून का अभ्यास करने का इरादा रखता है।यदि वह संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी भी बार एसोसिएशन का सदस्य बनने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे राज्य बार काउंसिल को सूचित करना होगा और आगे यह बताना होगा कि वह राज्य बार काउंसिल या स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ कैसे उठाएगा।इस संबंध में राज्य बार काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा।नियम 8.4 (iv) के अनुसार, प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक अधिवक्ता को अध्यक्ष/सचिव या एसोसिएशन के किसी अन्य विधिवत अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक है, कि आवेदक संबंधित बार एसोसिएशन का एक प्रामाणिक सदस्य है और उसने लॉ प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है।इसी तरह अभ्यास को फिर से शुरू करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव का एक प्रमाण पत्र, जिसके बारे में वह बार को बताने का इरादा रखते हैं।

सदस्य बनना आवश्यक है।इन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे दोहराया गया है:

"4. परिभाषाएँ।-

(ई) राज्य बार काउंसिल का अर्थ है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 3 (1) (ए) के तहत परिभाषित राज्य बार काउंसिल।(छ) किसी दिए गए क्षेत्र/नगर/शहर के बार एसोसिएशन का अर्थ है एक क्षेत्र/क्षेत्र और अधिवक्ताओं का अदालत कार्य आधारित संघ, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम(अधिनियमसं. 1860 का 21) या न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/व्यक्तियों या कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए सक्षम किसी अन्य प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के पूरे या हिस्से के संदर्भ में परिभाषित अपना क्षेत्र/क्षेत्र नहीं है, जिसके समक्ष इसके सदस्य सामान्य रूप से कानून का अभ्यास करते हैं और इसमें विशेष रूप से कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले बार एसोसिएशन शामिल हैं। प्राधिकरणों/न्यायाधिकरणों/बोर्डों आदि के संबंध में आयकर, निगमित कानून, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क कानून आदि।

अध्याय **II**

स्थानीय बार संगठन

6. बार एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए अधिवक्ता जहां वह सामान्य रूप से कानून का अभ्यास करता है **-**

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 22 के तहत नामांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एक अधिवक्ता को बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है, जहां वह सामान्य रूप से कानून का अभ्यास करता है या कानून का अभ्यास करने का इरादा रखता है।और यदि कोई अधिवक्ता संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी बार एसोसिएशन का सदस्य बनने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे राज्य बार काउंसिल को इसकी सूचना देनी होगी और उसे यह बताना होगा कि उसे राज्य बार काउंसिल या स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा।इस संबंध में राज्य बार काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई अधिवक्ता एक बार एसोसिएशन को छोड़ देता है और अभ्यास के स्थान में परिवर्तन के कारण या कानून के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण दूसरे में शामिल हो जाता है, तो वह राज्य बार काउंसिल को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ इस तरह के परिवर्तन की सूचना देगा, जिसका वह सदस्य है। के रूप में छोड़ने का ऐसा तथ्य शामिल होने के

बारे में एक महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त बार काउंसिल को स्वतंत्र रूप से सूचित किया जाएगा।बार एसोसिएशन इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त होने के लिए संबंधित बार काउंसिल को आवेदन करेंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में वे स्थित हैं।मान्यता केवल ऐसे बार एसोसिएशन को दी जाएगी जो इन नियमों में परिभाषित बार एसोसिएशन की परिभाषा के भीतर आता है।

8. 12 जून**, 2010** को या उससे पहले नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा **"**अभ्यास करने के लिए प्रमाण पत्र और अभ्यास के स्थान**"** के सत्यापन के लिए आवेदनः

विद्या सम्बन्धी वर्ष 2009-2010 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) में कानून में स्नातक और उसके बाद 12 जून, 2010 को या उसके बाद "अधिवक्ताओं की सूची" में नामांकित एक अधिवक्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 के तहत "प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए और राज्य बार काउंसिल से ऐसे "प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र" के सत्यापन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें वह नियम 9 के तहत एक वकील के रूप में नामांकित है।

"अधिवक्ताओं की सूची" में नामांकित विद्या सम्बन्धी वर्ष 2010 से पहले कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले अधिवक्ता को राज्य बार काउंसिल से "प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र और प्रैक्टिस का स्थान" के सत्यापन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें वह इन नियमों/नामांकन की तारीख के प्रवर्तन के 6 महीने की अवधि के भीतर इस नियम के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित है।

अभ्यास का सत्यापित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ए कॉलम I और कॉलम II में दिया गया है, जिसमें राज्य बार काउंसिल को सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा किया जाएगा, जिसके साथ वह नामांकित है।

ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, घोषणा, शुल्क आदि होंगेः- (i) बैंक ड्राफ्ट/खाता प्राप्तकर्ता बैंक चेक या नकद के माध्यम से Rs.100-(केवल एक सौ रुपये) की राशि में सत्यापन शुल्क/प्रक्रिया शुल्कः-

ए। सचिव राज्य बार काउंसिल, जिसके साथ आवेदक

नामांकित (या इसका भुगतान नकद में भी किया जा सकता है);

इसमें से रु. 100/-, सचिव, राज्य बार काउंसिल रुपये की राशि भेजेगा। 20/- संबंधित बार एसोसिएशन को और रु। 30/- बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बाकी रु। 50/- राज्य बार काउंसिल के खाते में रखा जाना है।

(ii) इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 'ए' के कॉलम II में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा;

(iii) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव या एसोसिएशन के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा सत्यापित दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, जो बार एसोसिएशन द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत हैं, जिसमें आवेदक सदस्य है, या राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधिवत अधिकृत राज्य बार काउंसिल के सदस्य द्वारा;

(iv) अध्यक्ष/सचिव या एसोसिएशन के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा जारी फॉर्म ए कॉलम III में प्रमाण पत्र, जो बार एसोसिएशन द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत है/इस प्रभाव के लिए कि आवेदक अधिवक्ता संबंधित बार एसोसिएशन का एक प्रामाणिक सदस्य है और उसने लॉ प्रैक्टिस या राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधिवत अधिकृत राज्य बार काउंसिल के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं छोड़ा है।

यदि आवेदक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 22 के तहत नामांकन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से अलग-अलग समय पर अलग-अलग बार संघों का सदस्य रहा है, तो ऐसे प्रमाण पत्र अलग-अलग बार संघों के अध्यक्षों/सचिवों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें से आवेदक अलग-अलग समय पर सदस्य रहा है।यदि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की खंड 22 के तहत नामांकन का प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से पांच (5) साल से अधिक पहले दिया गया था, तो ऐसे प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र को केवल पांच (5) साल की अवधि तक सीमित रखने की आवश्यकता है।

बशर्ते कि यदि किसी भी स्तर पर यह स्थापित हो जाता है कि ऐसे किसी प्राधिकरण ने यह जानने के बाद भी कि अधिवक्ता व्यवहार में नहीं है, जानबूझकर फॉर्म 'ए' के कॉलम III में प्रमाण पत्र जारी किया है, तो राज्य बार काउंसिल ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले ऐसे प्राधिकरण के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कि उपरोक्त आवेदन आवेदक द्वारा सभी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ या तो राज्य बार काउंसिल के कार्यालय में उचित रसीद के खिलाफ हाथ से दायर किया जा सकता है या पंजीकृत डाक के तहत सचिव को या बार एसोसिएशन के माध्यम से भेजा जा सकता है, जिसका वह सदस्य है।

28. अभ्यास फिर से शुरू करना

यदि कोई अधिवक्ता जिसका नाम नियम 20.4 के तहत प्रकाशित "गैर-वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" में शामिल किया गया है, परिवर्तित परिस्थितियों में कानूनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करने का इरादा रखता है, तो वह राज्य बार काउंसिल को आवेदन कर सकता है कि उसका नाम ऐसी सूची से निकाला जा सकता है।

फिर से शुरू करने के लिए आवेदन फॉर्म सी में 2,000/- रुपये के फिर से शुरू करने के शुल्क और घोषणा के साथ किया जाएगा।

इस तरह के आवेदन को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी फॉर्म ए के कॉलम III में एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें से आवेदक कानून में अभ्यास करने के लिए सदस्य बनने का इरादा रखता है।

राज्य बार काउंसिल इस तरह के आवेदन को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासनिक समिति को भेजेगी जो इस तरह के आवेदन को अनुमति देने या खारिज करने के लिए एक उचित आदेश पारित कर सकती है, बशर्ते कि इस तरह के आवेदन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब प्रशासनिक समिति संतुष्ट हो कि आवेदक का कानूनी अभ्यास फिर से शुरू करने का इरादा प्रामाणिक है।

यदि फिर से शुरू करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो आवेदक का नाम "गैर-अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं" की सूची से बाहर कर दिया जाएगा और इस तरह के बहिष्कार को नियम 20.3 क "गैर-अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" द्वारा प्रदान किए गए अनुसार विधिवत अधिसूचित और प्रकाशित किया जाएगा।

कि नियम 28.4 के तहत प्रकाशन की तारीख से, नियम 21 के तहत आवेदक द्वारा झेली गई सभी अक्षमताएं नहीं बचेंगी, लेकिन वह उस अवधि के लिए किसी भी लाभ/विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जो उसे नियम 21 के तहत "गैर-अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" में रखा गया था।

Rs.2000-में से Rs.1000 की राशि का उपयोग राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के उद्देश्य से किया जाएगा और Rs.500-को संबंधित को हस्तांतरित किया जाएगा।

एसोसिएशन और रु। 500/- का उपयोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किया जाएगा।"

बार संघों की भूमिका और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालयः

(34) हाल के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है और अपने सदस्यों के आचरण को विनियमित करने और चूक के लिए जवाबदेह होने में बार एसोसिएशनों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। विशाखा दिशानिर्देशों को लागू करने से लेकर यह निर्देश देने तक कि हड़ताल का आह्वान नहीं किया जाएगा, बार एसोसिएशनों को जवाबदेह ठहराया गया है।

मेधा कोतवाल लेल बनाम भारत संघ 3, कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ 4

(35) न्यायाधीश के प्रशासन के लिए तंत्र के हिस्से के रूप में अदालत से जुड़े बार संघों के कामकाज को रेखांकित किया गया था

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी. डी. कौशिक 5

निम्नलिखित शब्दों में:"28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत से जुड़े बार एसोसिएशन अन्य वकीलों के संघों जैसे लॉयर्स फोरम, ऑल इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन आदि से अलग एक अलग वर्ग का गठन करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा संबंधित अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।कोर्ट-एनेक्स्ड बार एसोसिएशन न्यायाधीश के प्रशासन के लिए तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं।जैसा कि अक्सर कहा जाता है, पीठ और बार रथ के दो पहियों की तरह हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता है।अदालत से जुड़े बार एसोसिएशन संबंधित बार एसोसिएशन के नाम के हिस्से के रूप में अदालत के नाम से शुरू होते हैं।यही कारण है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन आदि हैं। इस तरह के बार एसोसिएशन की प्रकृति का अनिवार्य रूप से अर्थ और तात्पर्य है कि यह एक ऐसा संघ है जो नियमित रूप से अदालत में काम करने वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और अदालत में अपने सदस्यों के

उचित आचरण और अदालत को उचित सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस पर विचार करते हुए, न्यायालय संघ के कार्यालय, पुस्तकालय और कक्ष 3 (2013) 1 एस. सी. सी. 297 जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थान प्रदान करता है।

4 (2006) 9 एससीसी 295

5 (2011) 13 एससीसी 774

कई अन्य सुविधाओं के अलावा अदालत, पार्किंग स्थल और कैंटीन में नियमित रूप से अभ्यास करने वाले सदस्यों के लिए रियायती दरों पर।अदालत से जुड़े बार एसोसिएशनों द्वारा आयोजित समारोहों में न्यायाधीश भाग लेते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और समस्याओं का पता लगाते हैं, यदि कोई हो, तो उन्हें हल करने के लिए और इसके विपरीत।इस प्रकार बार एसोसिएशन के सदस्यों और न्यायाधीशों के बीच नियमित बातचीत होती है।नियमित रूप से

काम करने वालों को अदालत के अधिकारियों के रूप में माना जाता है और उन पर उचित विचार किया जाता है।"

इस मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के नियम 18 के संशोधन को बरकरार रखा, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, यदि ऐसे सदस्य ने किसी भी उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के अधिकार का प्रयोग किया था।

(36) सुधा बनाम चेन्नई अधिवक्ता संघ में। 6, सर्वोच्चअदालत ने एक बार एसोसिएशन के उप कानूनों को चुनौती दी, जिसने चुनावों में अपने सदस्यों की भागीदारी के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं।यह निर्धारित किया गया था कि दो साल से कम की प्रैक्टिस करने वाला एसोसिएशन का कोई सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा और एसोसिएशन का कोई सदस्य जिसने तीन साल की प्रैक्टिस नहीं की है, वह चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। बार के सदस्यों के लिए एक प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता लगाई गई थी।चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती थी।

(37) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-वकीलों को बार संघों के चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए किए गए इन संशोधनों को शायद ही कानूनी पेशे के खिलाफ माना जा सकता है।न्यायाधीशालय ने देखा कि कानूनी पेशा अन्य व्यवसायों से अलग है क्योंकि वकील जो करते हैं, वह न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि न्यायाधीश के प्रशासन को भी प्रभावित करता है जो सभ्य समाज की नींव है।इस बात पर जोर दिया गया कि यह सुनिश्चित करना बार एसोसिएशनों का कर्तव्य है कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के समय अधिवक्ताओं द्वारा कोई गैर-पेशेवर और/या अशोभनीय आचरण न हो।न्यायालय की टिप्पणियां जो वर्तमान संदर्भ में निर्देशात्मक हैं, क्योंकि ऐसी कुछ शर्तें विवादित नियमों का हिस्सा हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

"40. कानूनी पेशा एक गंभीर और गंभीर पेशा है।यह एक महान आह्वान है और वे सभी जो 6 (2010) 14 एस. सी. सी. 114 से संबंधित हैं।ये इसके सम्मानित सदस्य हैं।हालाँकि पेशे में प्रवेश केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करके किया जा सकता है, लेकिन एक पेशेवर के रूप में सम्मान उसके सदस्यों द्वारा अदालत के अंदर और बाहर उनके अनुकरणीय आचरण द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए।कानूनी पेशा अन्य व्यवसायों से अलग है क्योंकि वकील जो करते हैं, वह न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि न्यायाधीश के प्रशासन को भी प्रभावित करता है जो सभ्य समाज की नींव है।समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के एक प्रमुख सदस्य और एक बुद्धिमान नागरिक दोनों के रूप में, वकील को अपने पेशेवर और अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आचरण करना पड़ता है।आवश्यकता पड़ने पर वकीलों की ताकत दिखाने के लिए बार के सदस्यों के विभिन्न संघों का गठन किया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव में वोट का प्रयोग करते समय वकील को खुद को अनुकरणीय तरीके से संचालित करना चाहिए।जो लोग पेशे के उच्च स्तर के बारे में चिंतित हैं, उन्हें यह देखने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से हो।

41. कई बार यह देखा गया है कि जो लोग वकील नहीं हैं, वे केवल काला कोट पहनकर एसोसिएशन कक्ष में प्रवेश करते हैं क्योंकि चुनाव के समय भावनाएं बढ़ रही होती हैं।इस तरह के तत्व स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं और अधिवक्ताओं के संघ का नाम खराब करते हैं।इसलिए, ऐसे तत्वों को रोकने के लिए उपनियमों में संशोधन किए गए हैं। एसोसिएशन के उपनियमों में किए गए उन संशोधनों को शायद ही सामान्य रूप से कानूनी बिरादरी के खिलाफ और विशेष रूप से बार के कनिष्ठ सदस्यों के खिलाफ माना जा सकता है।

42. प्रत्येक समाज या संघ में कुछ आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिए कि मतदान किस तरीके से किया जाना चाहिए और कौन मतदान करने में सक्षम होगा।अधिवक्ताओं के संघों से इस अवसर पर आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्यायाधीश के प्रशासन में हस्तक्षेप को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।यह सुनिश्चित करना संघों का कर्तव्य है कि संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के समय अधिवक्ताओं द्वारा कोई गैर-पेशेवर और/या अशोभनीय आचरण न हो।यह उनका कर्तव्य होने के कारण यह था।

एसोसिएशन के उपनियमों में संशोधन करना आवश्यक है।

43. यह निर्धारित करने वाला संशोधन कि दो साल से कम की प्रैक्टिस करने वाला एसोसिएशन का कोई सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा या एसोसिएशन का कोई सदस्य जिसने तीन साल की प्रैक्टिस नहीं की है, वह चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा, उचित है और बार के सदस्यों की स्थिति और छवि को बढ़ाने के लिए है। ये प्रतिबंध अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं कि कोई गैर-पेशेवर और/या अशोभनीय आचरण न हो।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जिन अन्य संशोधनों पर आपत्ति जताई है, वे भी संघ के सदस्यों पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

44. संशोधित उपनियमों का खंड 12 मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मानदंड को संदर्भित करता है और इसे अनुचित नहीं माना गया है।संशोधित उपनियमों के खंड 10 में बार के सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता निर्धारित की गई है। प्रवेश शुल्क के रूप में 2000 रुपये के प्रिस्क्रिप्शन और 1000 रुपये के साथ-साथ 2000 रुपये की वार्षिक सदस्यता को शायद ही अत्यधिक माना जा सकता है।जो अधिवक्ता संघ का सदस्य है, वह यह महसूस कर सकता है कि संघ को अपने सदस्यों की ओर से कई खर्च करने पड़ते हैं।दैनिक निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें उचित वेतन दिया जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश शुल्क या वार्षिक सदस्यता के प्रिस्क्रिप्शन को शायद ही अत्यधिक माना जा सकता है।कई बार एसोसिएशनों में यह भी देखा गया है कि कुछ सदस्य प्रवेश शुल्क या वार्षिक सदस्यता का भुगतान किए बिना एसोसिएशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आनंद लेते हैं।कुछ मामलों में यह पाया गया है कि कुछ अधिवक्ता शुरू में वार्षिक सदस्यता का भुगतान करके संघ के

सदस्य बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं करते हैं और संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का आनंद लेते रहते हैं।इन परिस्थितियों में, यह शर्त कि सदस्यता का नवीनीकरण न होने की स्थिति में, किसी सदस्य को अपनी सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए Rs.5000 की राशि का भुगतान करना होगा, शायद ही मनमाना माना जा सकता है।

45. फिर से खंड **17** जो चुनाव लड़ने के लिए राशि जमा करने का निर्देश देता है**,** उसे मनमाना नहीं माना जा सकता है।

चुनाव लड़ने के लिए कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसके परिणामस्वरूप अराजकता होने की संभावना है और अयोग्य तत्व स्थिति का लाभ उठाएंगे।अदालत में हल्के-फुल्के अंदाज में किसी ने उल्लेख किया कि अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है तो संघ के सभी सदस्य चुनाव लड़ेंगे और कोई मतदाता नहीं होगा।इसलिए, यह दलील कि चुनाव लड़ने के लिए जमा की जाने वाली राशि को उचित स्तर तक कम किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही उक्त खंड को अवैध या मनमाना माना जा सकता है।"

(38) दिल्ली उच्च न्यायालय ने P.K.Dash के मामले (सुपर) में इस तर्क को खारिज कर दिया कि बार एसोसिएशन पूरी तरह से निजी निकाय थे जो स्वेच्छा से अपने स्वयं के संविधान के साथ बनाए गए थे, इसलिए, अदालत, अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'एक बार एक वोट' सिद्धांत को लागू करने का आदेश नहीं दे सकती थी। न्यायाधीशालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशिक निर्णय लेने में अधिवक्ताओं की भूमिका के महत्व और न्यायाधीश के प्रशासन में अधिवक्ता संघों की भूमिका को देखते हुए, उन्हें उचित रूप से सार्वजनिक कार्य करने वाला कहा जा सकता है और न्यायाधीशालय यह निर्देश दे सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 'एक बार एक वोट' नियम को शामिल करने के लिए बार एसोसिएशन नियमों में संशोधन किया जाए।यह देखा गया:

"36. भारत में न्यायालयों में अधिवक्ताओं की इस स्थिति और न्यायिक निर्णय लेने में उनकी भूमिका के महत्व को देखते हुए, कानून द्वारा विनियमित नहीं होने वाले मामलों के संबंध में उनका आचरण "सार्वजनिक कार्यों" के रूप में वर्णित किए जाने से परे दिखाई दे

सकता है।फिर भी, ऐसा नहीं है।बार काउंसिल जैसे वैधानिक निकायों के अलावा प्रतिवादी जैसे बार एसोसिएशन भी अदालत के प्रशासन और कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।यह इस तथ्य से प्राप्त किया जा सकता है कि अदालत की प्रक्रिया ऐसे बार एसोसिएशनों के साथ परामर्श के

बाद तैयार की जाती है, महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय जैसे कि कक्ष आवंटित करने के नियम, सामान्य स्थानों का उपयोग, वाणिज्यिक स्थानों का आवंटन, उनकी पहचान (सभी वादकारी जनता और बार के सदस्यों के उपयोग के लिए) पार्किंग स्थल, अधिवक्ता अधिनियम के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए नीतियां और नियम, अक्सर, इन बार एसोसिएशनों से परामर्श और इनपुट के साथ, उनकी प्रतिनिधि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।ऐसे के भीतर कोई भी विवाद न्यायालय के कामकाज में संगठन का हमेशा प्रभाव पड़ता है।जनता के सदस्यों के साथ संघर्ष, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क-अदालत, अदालत परिसर, कक्ष आदि की सुरक्षा के लिए बार संघों द्वारा सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है।अक्सर, अदालत परिसर में बार के सदस्यों की व्यक्तिगत शिकायतों के लिए इन संघों की ओर से हस्तक्षेप और कुशलता से निपटने की आवश्यकता होती है, जिसकी अनुपस्थिति में में अदालत की कार्यवाही बाधित हो जाती है।इन सबसे ऊपर, बार एसोसिएशनों के चुनावों में अक्सर स्थगन के लिए बड़े पैमाने पर अनुरोध किए जाते हैं, और वादियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।अदालत की नीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने के लिए वोटों के लिए प्रचार करने में अनुशासन की आवश्यकता होती है और बार एसोसिएशनों द्वारा पर्चे और पर्चे, वक्ताओं के उपयोग आदि के रूप में क्या अनुमत है, अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह अदालत के कामकाज को भी गंभीर रूप से कमजोर कर देगा।ये दर्शाते हैं कि बार एसोसिएशन की गतिविधियों का मुख्य रूप से सार्वजनिक चरित्र होता है, और कई मामलों में, अदालत के कामकाज को प्रभावित कर सकता है।नतीजतन, यह माना जाता है कि इन कार्यवाहियों में मांगी गई राहत की प्रकृति आंतरिक रूप से न्यायालय के सार्वजनिक कामकाज से जुड़ी हुई है और उन्हें प्रभावित करती है।नतीजतन, वर्तमान कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य है।"

चर्चा:**(i)** क्या **2001** के नियम राज्य बार काउंसिल की नियम बनाने की शक्तियों अधिकारातीत हैं**?**

(39) सर्वोच्च न्यायाधीशालय के उपरोक्त कानूनों, नियमों और निर्णयों का संदर्भ स्पष्ट रूप से उस महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करता है जो बार एसोसिएशन न केवल न्यायाधीश के प्रशासन और आम तौर पर अधिवक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने में बल्कि उनके कल्याण के लिए वैधानिक या गैर-वैधानिक योजनाओं को लागू करने में भी निभाते हैं।वास्तव में ऐसी योजनाओं को बार एसोसिएशनों को संबद्ध किए बिना लागू करना असंभव होगा, क्योंकि यह केवल बार एसोसिएशन हैं जो पेशे के प्रत्येक अभ्यास करने वाले सदस्य तक पहुंचते हैं, उन्हें शामिल करते हैं और स्पर्श करते हैं।शायद यह इस तथ्य के अहसास में है कि खंड 6 (1) (डी. डी.) को 1961 के अधिनियम में 1993 (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ताकि राज्य बार काउंसिलों को अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(40) 2001 के अधिनियम के अनुसार, राज्य बार काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का सदस्य होने के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष का सदस्य बनने के लिए यह एक पूर्व शर्त है।खंड 16 के अनुसार, प्रत्येक बार एसोसिएशन, चाहे वह 2001 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले मौजूद हो या उसके बाद गठित हो, को राज्य बार काउंसिल के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।खंड 16 (3) के अनुसार मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संघ के नियमों और उपनियमों की एक प्रति, संघ के पदाधिकारियों के नाम और पते; संघ के सदस्यों की एक सूची जिसमें नाम, पता, आयु, नामांकन संख्या, नामांकन की तारीख और अभ्यास का सामान्य स्थान होना आवश्यक है।खंड 16 (4) के अनुसार, राज्य बार काउंसिल ऐसी जांच करने के बाद, जो उसे आवश्यक लगे, एसोसिएशन को मान्यता दे सकती है।किसी संगठन की मान्यता के संबंध में बार काउंसिल का निर्णय अंतिम बना दिया गया है।इस अधिनियम की खंड 17 प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन और राज्य अधिवक्ता संघ को हर साल 15 अप्रैल को या उससे पहले राज्य बार काउंसिल को अपने सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है।खंड 17 (2) (सी) के अनुसार, प्रत्येक राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ को राज्य बार काउंसिल को ऐसे अन्य मामलों के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो समय-समय पर राज्य बार काउंसिल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

(41) 2001 के अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार को उसकी धारा 35 और 36 के अनुसार प्रदान की गई है।हालाँकि, 1961 के अधिनियम की धारा 15 में अधिनियम के खंड II के मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, जिसमें धारा 3 से 15 शामिल हैं, बार काउंसिलों को प्रदान की गई है जिसमें भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिल शामिल हैं।यद्यपि खंड 15 (3) के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित न हो।

(42) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 1961 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य बार काउंसिल को बार एसोसिएशनों के चुनावों को विनियमित करने के लिए कोई नियम बनाने का अधिकार देता है, जो निजी स्वैच्छिक संघ हैं, जबकि राज्य बार काउंसिल का रुख यह है कि वह 1961 के अधिनियम की खंड 15 और 2001 के अधिनियम की खंड 16,17 और 18 के साथ पठित खंड 6 (1) (डीडी), 6 (1) (एच), 6 (1) (आई) के प्रावधानों से ऐसी शक्ति प्राप्त करती है।

(43) एक बात स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी प्रावधान विशिष्ट शब्दों में राज्य बार काउंसिलों को बार एसोसिएशनों के चुनावों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है।सवाल यह है कि क्या ऐसी नियम बनाने की शक्ति का अनुमान धारा 122 के तहत दिए गए खंड 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामान्य नियम बनाने की शक्ति से लगाया जा सकता है।

15(1) 1961 के अधिनियम की खंड 6 (1) (डी. डी.), जो कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए बार एसोसिएशनों के विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है, विशेष रूप से बार काउंसिल के कार्यों को ध्यान में रखते हुए; खंड 6 (1) (एच) जो अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान किए गए अन्य सभी कार्यों को करने से संबंधित है और खंड 6 (1) (आई) जो बार काउंसिल को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने का अधिकार देती है।

(44) एक अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति का दायरा न्यायिक निर्णयों का विषय रहा है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अधीनस्थ विधान की वैधता पर विचार करते समय, सक्षम अधिअधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना होगा, और यह भी कि अधिअधिनियम केतहत किस क्षेत्र पर शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और फिर यह तय करना होगा कि अधीनस्थ विधान मूल क़ानून के अनुरूप है या नहीं।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करते हुए कि बनाए गए नियम मूल अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्र के भीतर हैं, न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण देने में उचित होगा।

(45) भारत संघ बनाम एस. श्रीनिवासन 7 में, सुप्रीम कोर्ट ने

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:30. इस संदर्भ में, टी. एन. राज्य बनाम के एक परिच्छेद का उल्लेख करना उचित होगा।पी. कृष्णमूर्ति जिसमें यह इस प्रकार आयोजित किया गया है:(एस. सी. सी. पी. 529,

पैरा 16)

"16. अधीनस्थ विधान की वैधता पर विचार करते हुए न्यायालय को सक्षम अधिअधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना होगा, और उस क्षेत्र पर भी विचार करना होगा जिस पर अधिअधिनियम के तहत शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और फिर यह तय करना होगा कि अधीनस्थ विधान मूल क़ानून के अनुरूप है या नहीं। जहाँ कोई अधिनियम क़ानून के अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है, तो निश्चित रूप से, न्यायालय का कार्य सरल और आसान है।लेकिन जहां तर्क यह है कि नियम की विसंगति या गैर-अनुरूपता सक्षम अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मूल अधिनियम के उद्देश्य और योजना के साथ है, अदालत को अयोग्यता घोषित करने से पहले सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।"32. कानून के उपरोक्त उच्चारण को ध्यान में रखते हुए, हम सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना उचित समझते हैं। नियम, उद्देश्यपूर्ण निर्माण की अवधारणा और प्रत्यायोजित निकायों में निहित विवेक।"

(46) प्रताप चंद्र मेहता बनाम स्टेट बार काउंसिल ऑफ

एम. पी. 8, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1961 के अधिनियम की खंड 15 के तहत नियम बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल की शक्तियों की जांच करते हुए अधिनियम के

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 6 में निहित विधायी अधिदेश के अनुसार कार्य करने की राज्य बार परिषदों की जिम्मेदारी बहुत व्यापक अर्थ और दायरे की थी।राज्य बार काउंसिल को नियम बनाने के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को लगन से कर सके और अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी चीजें कर सके। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस शक्ति को सख्त व्याख्या देना कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा, जब तक कि विशिष्ट भाषा द्वारा दायरे में प्रतिबंधित न किया जाए।यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले प्रावधान एक सामान्य प्रकृति के हैं जैसे कि धारा 15 (1) जिसमें बार काउंसिल को "इस खंड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए" नियम बनाने की आवश्यकता होती है और धारा 15 (2), जो आगे सामान्य शब्दों का उपयोग करती है जिसके द्वारा बार काउंसिल को "विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" नियम बनाने का अधिकार है।इस बात पर जोर दिया गया कि नियम बनाने की शक्ति को एक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के बजाय एक व्यापक दायरा दिया जाना चाहिए ताकि विधायी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“48. हमारे विचार में, धारा 6 (1) (एच) और 6 (1) (आई) को संयुक्त रूप से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए।हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि खंड 6 (1) (जी) में "अपने सदस्यों के चुनाव के तरीके" अभिव्यक्ति को एक सीमित अर्थ क्यों दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से खंड 6 (1) (एच) और 6 (1) (आई) के आलोक में।अधिनियम की खंड 6 में निहित विधायी अधिदेश के अनुसार कार्य करने की राज्य बार परिषदों की जिम्मेदारी का बहुत व्यापक अर्थ और दायरा है।इसे सीमित अर्थ देने या सख्त व्याख्या से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।राज्य बार काउंसिल को नियम बनाने के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को लगन और पूरी तरह से कर सके और अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी चीजें कर सके। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल भी अध्याय 2 के तहत निर्धारित किया गया है, जो इस

तारीख से पांच साल का होगा।चुनाव के परिणाम का प्रकाशन।चुनाव की व्यवस्था करने में विफलता पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना पड़ता है।

8 (2011) 9 एससीसी 573

49. खंड 15 (2) में यह प्रावधान है कि पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतदाता सूची तैयार करने और परिणाम प्रकाशित करने के तरीके का प्रावधान करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।खंड 15 (2) (सी) के संदर्भ में, बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव और किसी भी चुनावी विवाद का फैसला करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका प्रदान किया गया है।"सभापति के चुनाव का तरीका" अभिव्यक्ति फिर से एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे इसके व्यापक अर्थ में समझने की आवश्यकता है।राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा इस प्रकार बनाए गए नियम अधिवक्ता अधिनियम की खंड 15 (3) के संदर्भ में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित होने पर ही प्रभावी होंगे।

50. भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 15 के तहत नियम बनाने की राज्य विधिज्ञ परिषद की शक्ति का अर्थ इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में, अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधानों के तहत विधायिका द्वारा बताए गए वैधानिक प्रावधानों और अन्य उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसे अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची तैयार करने, पेशे को कानूनी व्यवसायियों के एक खंड में एकीकृत करने, खंडीकरण में एकरूपता प्रदान करने और प्रत्येक राज्य में और पूरे भारत के लिए एक स्वायत्त बार काउंसिल बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।राज्य बार काउंसिल का कार्य सदस्यों के एक निर्वाचित निकाय द्वारा और उन पदाधिकारियों द्वारा किया जाना है, जिन्हें उक्त परिषद के इन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया है।अधिनियम के उपरोक्त उद्देश्यों के साथ प्राप्त विधायी इरादे को प्राप्त किया जाना चाहिए और राज्य और अखिल भारतीय बार परिषदों में पूर्ण और स्वतंत्र लोकतांत्रिक कार्य होना चाहिए।

51. नियम बनाने की शक्ति को एक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के बजाय एक व्यापक दायरा दिया जाना चाहिए ताकि विधायी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।बार काउंसिलों द्वारा किए जाने वाले कार्य और जिस तरह से ये राकेश पूनिया बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से पता चलता है कि चुनाव प्रक्रिया और इसके सभी कार्यों के प्रदर्शन और पेशेवर आचरण के मानकों दोनों में लोकतांत्रिक मानकों का पालन करने की आवश्यकता है।दूसरे शब्दों में, अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को एक ऐसी व्याख्या की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इसे विफल कर देगी और राज्य बार काउंसिलों के शासन और संचालन का मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल देगी।

52. अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान राज्य बार काउंसिल के लिए नियम बनाने की शक्ति का एक स्रोत हैं और यह उस शक्ति को सख्त व्याख्या देने के लिए कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा, जब तक कि विशिष्ट भाषा द्वारा दायरे में प्रतिबंधित न हो। यह विशेष रूप से तब होता है जब ऐसी शक्ति को प्रत्यायोजित करने वाले प्रावधान सामान्य प्रकृति के होते हैं, जैसे कि अधिनियम की धारा 15 (1), जिसमें बार काउंसिल को "इस खंड के उद्देश्यों को पूरा करने" के लिए नियम बनाने की आवश्यकता होती है और धारा 15 (2), जो आगे सामान्य शब्दों का उपयोग करती है और स्पष्ट रूप से बताती है कि बार काउंसिल को "विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" नियम बनाने का अधिकार है।यदि कोई अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (ए), (सी), (जी), (एच) और (आई) के प्रावधानों को पढ़ता है, तो यह स्पष्ट है कि इसके तहत नियम बनाना राज्य बार काउंसिलों के कामकाज के संचालन का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेगा और उक्त परिषदों में लोकतांत्रिक शासन के मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।चूँकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी एक प्रतिनिधि निकाय द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात अधिवक्ताओं द्वारा जो परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों में अधिवक्ताओं/मतदाताओं द्वारा दिए गए विश्वास के आधार पर, ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि वह निर्वाचित निकाय ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ "अविश्वास

प्रस्ताव" पेश नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब नियम इसकी अनुमति देते हैं।

58. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किसी प्रावधान को व्यापक अर्थ देने से पहले अधिनियम की भाषा की जांच की जानी चाहिए।न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य को कायम रखने के लिए प्रावधान को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण देने में उचित होगा, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि बनाए गए ऐसे नियम मूल 126 द्वारा सीमित क्षेत्र के भीतर हैं।एक्ट करें। यह भी स्पष्ट है कि जब ऐसे प्रतिनिधि निकायों में विवेकाधिकार निहित होता है, तो प्रत्यायोजित विधान के लिए दिशानिर्देशों को स्पष्ट करना हमेशा आत्यन्तिक रूप आवश्यक नहीं हो सकता है।ऐसे मामलों में, बनाए गए नियम की भाषा के साथ-साथ जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, वे न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारक होंगे।

60. उद्देश्यपूर्ण निर्माण, काफी हद तक, वर्तमान मामले में उठाए गए विवाद को हल करने में मदद करेगा।अधिवक्ता अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषदों का लोकतांत्रिक और सामंजस्यपूर्ण कार्यकरण है। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि नियम 122-ए के प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम की खंड 15 के दायरे और दायरे और उस मामले के लिए, उस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के खिलाफ कैसे आते हैं। इसके विपरीत, वे मूल अधिनियम की योजना के अनुरूप हैं।

(47) उपरोक्त विचारों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि राज्य बार काउंसिल को उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र में बार एसोसिएशनों के चुनावों से संबंधित मामलों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है।वास्तव में ऐसे नियमों को तैयार करना ऊपर उल्लिखित अधिनियमों और नियमों द्वारा प्रमाणित व्यापक विधायी योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता मानी जा सकती है, जिसमें राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशनों को केंद्रीय भूमिका सौंपी गई है और साथ ही न्यायाधीश के प्रशासन में बार एसोसिएशनों की

भूमिका और महत्व को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसोसिएशन वास्तव में अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय द्वारा भी ध्यान दिया और जोर दिया गया है।तदनुसार हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि नियम राज्य बार काउंसिल की नियम बनाने की शक्ति अधिकारातीत हैं।

(48) यह भी उल्लेखनीय है, जैसा कि बार काउंसिल की ओर से कहा गया है, कि पंजाब और हरियाणा में बार एसोसिएशनों के साथ व्यापक परामर्श के बाद नियम बनाए गए हैं। नियमों को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब और हरियाणा के सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों/सचिवों/पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई और उनके प्रस्तावों और सुझावों को प्राप्त करने के बाद ही नियम बनाए गए।इस प्रकार नियम इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों की व्यापक सहमति को दर्शाते हैं।

((ii) क्या बार के चुनावों का विनियमन संघ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

(49) इस मुद्दे पर कि क्या चुनावों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा एक पूरा जवाब दिया जाता है।उस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि विभिन्न अदालत परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए कक्षों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले नियमों को दिल्ली के पूरे क्षेत्र में एक कक्ष तक सीमित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, भले ही वे एक से अधिक बार एसोसिएशन के सदस्य हों। यह भी प्रार्थना की गई कि दिल्ली बार काउंसिल को दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों में 'वन बार वन वोट' की शुरुआत सुनिश्चित करनी चाहिए।'एक बार एक वोट' सिद्धांत की शुरुआत का विरोध करने वाले लोग संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत संघ बनाने के मौलिक अधिकार और अपनी इच्छा के अनुसार संघ के मामलों का संचालन करने के लिए परिणामी स्वायत्तता पर निर्भर थे।

(50) तदनुसार, न्यायालय को यह निर्णय लेना था कि क्या न्यायालय द्वारा 'एक बार एक वोट' को लागू करने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत अधिकारों का उल्लंघन करेगा।अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कि संघ या संघ बनाने का अधिकार आत्यन्तिक नहीं था, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन था, यह निम्नानुसार देखा गयाः-

“43. संगठन का अधिकार एक-आयामी नहीं है।इसे केवल किसी संगठन की सदस्यता चाहने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है।एसोसिएशन के पास अपनी सदस्यता को प्रतिबंधित करने या समोच्च बनाने का अधिकार है।किसी विशेष उद्देश्य के

लिए स्थापित किसी संगठन में कुछ भी अनुचित नहीं है, जो केवल उन लोगों को अपनी सदस्यता का पूरा लाभ स्वीकार करता है या प्रदान करता है जो उसके द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।जैसा कि पहले बताया गया है, संगठन का अधिकार संगठन के बने रहने के अधिकार को समाहित करता है।ए. पी. डेयरी विकास निगम महासंघ मामले (ऊपर) ने इस बात पर जोर दिया कि; साथ ही, न्यायालय ने कहा कि "केवल आधार 128 पर उनकी संरचना या कार्यप्रणाली में वैधानिक हस्तक्षेप पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। सांविधिक पदाधिकारी द्वारा व्यक्ति के संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन।कानून के माध्यम द्वारा संघ के कामकाज का विनियमन जीवन कार्यालयों और जीवन सदस्यता के लाभ तक नहीं बढ़ाया गया था।

पेरियार आत्म-सम्मान प्रचार संस्थान बनाम राज्य

तमिलनाडु**,** ए**.** आई**.** आर **1988** मैड। **27.**तोगुरू सुधाकर में

रेड्डी और एन**.** आर**.** वी**.**आंध्र प्रदेश राज्य**, 1992 (**एस**.** एल**.** टी**.** सॉफ्ट**) 604:**एयर

1994 एस. सी. 544, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ए. पी. सहकारी समितियों अधिनियम की धारा 31 के तहत सहकारी समितियों में महिलाओं को नामित करने की सरकार की शक्ति वैध थी। इस प्रावधान को भारत के संविधान के खंड 15 (3) को आगे बढ़ाने के लिए माना गया था।नतीजतन यह माना जाता है कि उत्तरदाता?यह कहना कि एक व्यक्ति एक वोट नियम लागू

करने से दिल्ली में बार एसोसिएशनों की आंतरिक स्वायत्तता प्रभावित होगी, बेमानी है।

44. यह न्यायालय सार्वजनिक कार्यों में शामिल निकायों के संबंध में याचिकाओं पर विचार करने और उन्हें निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में पहले ही काम कर चुका है।एक सहायक हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे प्रतिवादी संघों के आलोक में संबोधित करने की आवश्यकता है?तर्क यह है कि उनके संविधान/उपनियमों में संशोधन के तरीके को निर्धारित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए क्या न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है और ऐसी शर्तों को शामिल कर सकता है।यहाँ, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति एक वोट नियम लागू करने का तर्क शक्तिशाली है:यह अदालती कार्यवाही में व्यवस्था सुनिश्चित करता है, समय की हानि से बचाता है (जहां दी गई अदालतों में व्यवसायियों की ओर से स्थगन की मांग की जाती है, केवल उन्हें संबंधित अदालत (जिसमें संघ संलग्न है) और अन्य अदालतों में चुनाव में प्रचार करने और वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए) और कई बार

एसोसिएशनों के सदस्यों की परस्पर विरोधी या विभाजित वफादारी को समाप्त करता है, जो एक से अधिक बार एसोसिएशन में कार्यकारी पदों पर हो सकते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दिए गए न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी शिकायतों को उनके नियमित चिकित्सकों में से एक से उजागर किया जाए, जिनकी इसके कल्याण में हिस्सेदारी है।

45. अदालती समय को विनियमित करने और न केवल राकेश पूनिया बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में अधिवक्ताओं के लिए आचरण के नियमों को अनिवार्य करने में न्यायालय की भूमिका कार्यवाही का संचालन, लेकिन आम तौर पर न्यायालय के कामकाज से जुड़े मामलों में अधिवक्ता अधिनियम (2) की धारा 34 में पाया जा सकता है; यह प्रक्रिया और उसके मामलों, या उससे जुड़े मामलों को रिकॉर्ड न्यायालय (संविधान का अनुच्छेद 215) के रूप में विनियमित करने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का भी खंड है।अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति के विस्तार पर केवल इस स्पष्टीकरण पर जोर दिया जाता है कि इसमें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है:अर्थात्, उच्च न्यायालय "अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां

होंगी।"इनके साथ, और इसके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के आधार पर, इसके कार्यों की स्व-नियामक प्रकृति को मजबूत किया जाता है।इसलिए, जहां तक निकायों और संघों की गतिविधियों का संबंध है जो अदालत की प्रशासनिक और न्यायिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, किसी भी अधिनियमित कानून की अनुपस्थिति में ऐसी शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला कारक नहीं है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कक्ष आवंटन, आवंटन के नियमों, न्यायालय के कुछ प्रशासन से जुड़े निर्णयों में भागीदारी के संबंध में, बार एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।ये प्रभावी रूप से मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन हैं।इस मामले में, अदालत का यह आग्रह कि ऐसे संघों को व्यवस्था और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मानक मानदंडों का पालन करना चाहिए, अदालत के पीठासीन अधिकारी की दैनिक आधार पर कार्यवाही के संचालन को विनियमित करने की शक्ति के रूप में इसके कामकाज के लिए अंतर्निहित है।इसलिए, यह निवेदन कि इस न्यायालय के पास नियम बनाने की शक्ति नहीं है, या ऐसे नियम बनाने का आदेश नहीं है,

योग्यता से रहित है।यह न्यायालय इस संबंध में अपने निष्कर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा मजबूत है।

(51) हालांकि, उपरोक्त निर्णय 'एक बार एक वोट' की शुरुआत को अनिवार्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में दिया गया है, लेकिन इसका सिद्धांत बार एसोसिएशनों के चुनावों को विनियमित करने के लिए बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों पर लागू होगा, जो चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमित अंतराल पर चुनाव कराने के लिए घोषित उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं।

(52) इस प्रकार, एल. डी. के तर्क में कोई योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बार काउंसिल द्वारा केवल 130 नियम बनाए गए हैं। उपरोक्त उद्देश्य के साथ बार एसोसिएशनों के चुनावों को विनियमित करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (c) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

(iii) क्या नियम किसी भी प्रक्रियात्मक आधार पर अमान्य हैं?

(53) हम एल. डी. के तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 2015 के नियम अमान्य हैं क्योंकि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की कार्यवाही और एल. डी. द्वारा निर्दिष्ट संचार को ध्यान में रखते हुए। बार काउंसिल के वकील, हम पाते हैं कि नियमों की वैधता के लिए वैधानिक पूर्व-आवश्यकताओं का पालन किया गया था।नियम मसौदा समिति द्वारा तैयार किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा विचार किया गया, जिसने इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुमोदन के लिए भेजा।बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल हाउस ने 2.5.2015 पर आयोजित अपनी बैठक में इसे मंजूरी दी।

(54) इस प्रकार, याचिकाओं के वर्तमान समूह में कोई योग्यता नहीं है और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(55) यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाओं के वर्तमान सेट द्वारा, हमने केवल बार एसोसिएशनों के चुनावों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल की क्षमता के सवाल को संबोधित किया है और यह माना है कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा निष्पक्षता और पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे नियमों के निर्माण के माध्यम से बार एसोसिएशनों के चुनावों का विनियमन 1961 के अधिनियम के प्रावधानों अधिकारातीत नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (c) के तहत मूल अधिकार का भी उल्लंघन नहीं है।हम 2015 के नियमों के व्यक्तिगत प्रावधानों की वैधता में नहीं गए हैं क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत प्रावधान के संबंध में किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था।इसलिए इस निर्णय को 2015 के नियमों के प्रत्येक प्रावधान की वैधता पर राय और पुष्टि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सुनीता रानी